वर्ष 12 • अंक 264 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 24 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

गेहूं की रिकॉर्ड बुआई से लहलहाए खेत

एलएन मित्तल ▸▸ पृष्ठ 13

कर्ज चुकाने के लिए हिस्सा बेच रही आर्सेलरमित्तल

डॉलर रु. 71.20 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 78.90 (अपरिवर्तित) | सोना (10ग्राम) रु 38128 ▲ 160 रुपये | सेंसेक्स 41642.70 ▼ 38.90 | निफ्टी 12262.80 ▼ 09.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12336.00 ▲ 73.20 | ब्रेंट क्रूड 65.90 डॉलर ▼ 0.70 डॉलर

एक नज़र

मोदी ने की निवेश और वृद्धि पर कैबिनेट समिति की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और खर्च को बढ़ावा देने के उपाय तलाशने के लिए निवेश और विकास पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति की सोमवार को पहली बैठक की। सूत्रों ने कहा कि इस मंत्रिमंडलीय समिति का गठन नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा सत्ता संभालने के बाद जून में किया गया था। बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस समिति में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य एवं रेल मंत्री परयूष गोयल शामिल हैं।

स्विस खातों का ब्योरा साझा करने से मंत्रालय का इनकार

वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह स्विट्जरलैंड और भारत के साथ किए गए कर संधि के 'गोपनीयता प्रावधान' के तहत आते हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में मंत्रालय ने विदेश से प्राप्त काले धन का ब्योरा भी देने से मना कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि कर समझौते के तहत इस तरह की जानकारी का आदाल-प्रदान गोपनीयता प्रावधान के दायरे में आते हैं और विदेश की सरकार से मांगी गई या प्राप्त जानकारी को साझा करने पर सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 (1)(ए) और 8 (1)(एफ) से छूट मिली हुई है।

बोइंग ने अपने सीईओ को किया बर्खास्त

अमेरिकी की विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने सोमवार को अपने मुख्य कार्याधिकारी डेनिस म्युलेनबर्ग को उनके पद से हटा दिया। कंपनी ने अपने दो 737 मैक्स विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह कदम उठाया है। डेविड कैलहाउन उनकी जगह कंपनी के नए सीईओ होंगे और कैलहाउन की जगह लॉरेंस केलर नए चेयरमैन होंगे। बोइंग ने कहा कि म्युलेनबर्ग ने इस्तीफा दिया है, लेकिन यह भी कहा कि उन्होंने दबाव में यह कदम उठाया है।

व्यापार गोष्ठी

कारोबार के लिहाज से कैसा रहा साल 2019?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या झारखंड में जीत के बाद विपक्ष दे पाएगा भाजपा को मजबूत चुनौती

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**

आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद थमेगी देश में हिंसा? हां **66.66%** नहीं **33.34%**

आरओसी ने दी पुनर्विचार याचिका

टाटा संस का दर्जा बदलने के मामले में टिप्पणी पर एनसीएलएटी पहुंचा कंपनी पंजीयक

देव चटर्जी
मुंबई, 23 दिसंबर

कंपनी पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज), मुंबई ने टाटा समूह में चल रहे आंतरिक विवाद के मामले में राष्ट्रीय कंपनी अपील विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में पुनर्विचार याचिका दायर की है। आरओसी ने अपनी याचिका में एनसीएलएटी के आदेश से 'गैर-कानूनी' और 'आरओसी की मदद से' जैसे शब्द हटाए जाने की अपील की है। सितंबर 2017 में टाटा संस के एक 'पब्लिक लिमिटेड' कंपनी से 'प्राइवेट कंपनी' में तब्दील होने के मामले में एनसीएलएटी ने हाल में अपने आदेश में इन शब्दों का इस्तेमाल किया था।

18 दिसंबर को अपने आदेश में एनसीएलएटी ने आरओसी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि टाटा संस ने आरओसी के साथ मिलकर जल्दबाजी में टाटा संस को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर दिया। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में इसे अवैध करार दिया था। आरओसी ने याचिका में कहा है कि आदेश में कुछ तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटियां है। आरओसी ने एनसीएलएटी से आदेश में संशोधन करने की अपील की है ताकि आरओसी मुंबई के कदम को कंपनी कानून के नियमानुसार माना जाए।

याचिका की मुख्य बातें

- मिस्त्री बनाम टाटा विवाद में आरओसी एनसीएलटी और एनसीएलएटी में पक्षकार नहीं
- आरओसी को पक्ष रखने का अवसर दिए बिना एनसीएलएटी ने गंभीर शब्दों का किया इस्तेमाल
- आरओसी ने टाटा को पब्लिक से प्राइवेट बनाने में नहीं की मदद
- 'गैर-कानूनी' शब्द हटाने के लिए आदेश में संशोधन की अपील

आरओसी ने कहा कि टाटा संस के पूर्व कार्यकारी चेयरमैन साइरस मिस्त्री की निवेश कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई और बाद में एनसीएलएटी दिल्ली में दायर याचिका में वह पक्षकार नहीं था। आरओसी ने कहा कि एनसीएलएटी द्वारा आदेश देने से पहले उसे उसकी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा था कि न्यायाधिकरण का आदेश आने से पहले ही आरओसी ने अपने प्रमाणपत्र में 'पब्लिक' शब्द हटा दिया था और टाटा संस लिमिटेड को 'प्राइवेट' का दर्जा दे दिया था।

एनसीएलएटी ने कहा, 'इससे साबित होता है कि 24 अक्टूबर 2016 को मिस्त्री को कार्यकारी चेयरमैन और टाटा कंपनियों के निदेशक पद से बर्खास्त करने से बाद भी मामले विचाराधीन रहने के बावजूद टाटा संस और इसके निदेशकमंडल ने जल्दबाजी में कदम उठाया और कंपनी को पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने के लिए कंपनी निबंधक के पास पहुंच गए। यह पूरी प्रक्रिया कानून के खिलाफ और तथ्यों से परे था।'

एनसीएलएटी ने कहा था कि टाटा संस और इसके निदेशकमंडल द्वारा जल्दबाजी में टाटा संस को 'पब्लिक कंपनी' से 'प्राइवेट कंपनी' में बदलने का निर्णय कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 14 के तहत नहीं किया गया था। एनसीएलएटी ने कहा था कि अपील दायर करने से ठीक पहले आनन-फानन में लिए गया निर्णय दिखाता है कि टाटा ट्रस्ट के नामित सदस्यों और अन्य निदेशकों/सदस्यों ने अल्पांश शेयरधारकों सहित अन्य सदस्यों के हितों के खिलाफ कदम उठाया था।

एनसीएलएटी ने उस समय आरओसी की आलोचना की थी और कहा कि आरओसी का कदम कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 14 के खिलाफ और अल्पांश शेयरधारकों और डिपॉजिटरों के हितों के अनुरूप नहीं था, इसलिए यह पूरी कवायद गैर-कानूनी करार दी जाती है।

आरबीआई: बिक्री से ज्यादा खरीदे बॉन्ड

अनूप रॉय
मुंबई, 23 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पहली बार एक ही साथ खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत बॉन्ड की खरीद एवं बिक्री की। आंकड़ों के अनुसार आरबीआई ने इस दौरान बेचने के मुकाबले अधिक संख्या में बॉन्ड की खरीदारी की। आरबीआई ने 10 वर्ष की अवधि के 10,000 रुपये मूल्य तक के बॉन्ड खरीदने और इतनी ही रकम मूल्य तक के 4 छोटी अवधि के बॉन्ड की बिक्री की योजना तैयार की थी।

नीलामी के नतीजों से पता चलता है कि एक ओर केंद्रीय बैंक ने जहां 10 वर्ष की अवधि की बॉन्ड श्रेणी में पूरी खरीदारी कर ली, वहीं अगले एक वर्ष में परिपक्व होने वाले 6,825 करोड़ रुपये मूल्य के 4 छोटी अवधि के बॉन्ड की बिक्री की। इस लेनदेन के लिए बाजार की अवधि आधे घंटे तक बढ़ा दी गई।

बाजार में ऐसी चिंता जताई जा रही थी कि छोटी अवधि के बॉन्ड की बिक्री से पर्याप्त नकदी उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ जाएगा जैसा कि केंद्रीय बैंक कुछ ही चाह रहा है। हालांकि बॉन्ड कारोबारियों ने कहा कि आंशिक बिक्री से छोटी अवधि की प्राप्तियों पर असर नहीं होगा। वास्तव में आरबीआई प्राप्तियों को देखकर असहज दिखा। 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले वाले बॉन्ड पर प्राप्ति 6.5462 प्रतिशत रह गई, जो कारोबार बंद होने के स्तर 6.5680 प्रतिशत से थोड़ी कम दर्ज की गई। पिछले सप्ताह ओएमओ की घोषणा से पहले 10 वर्ष की अवधि वाले बॉन्ड पर प्राप्तियां 6.75 प्रतिशत थीं। 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड की खरीदारी के लिए आरबीआई को 20,826 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्ताव आई। छोटी अवधि के बॉन्ड के लिा आरबीआई को करीब 20,330 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्ताव आए। चार बॉन्ड में प्राप्ति 5.22 से 5.578 प्रतिशत के बीच थी, जो उनके मौजूदा बाजार दर से करीब 4 से 5 आधार अंक अधिक रहीं।

- आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड खरीदने की अधिसूचना जारी की थी
- 20,826 करोड़ रुपये मूल्य की पेशकश आई
- आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपये स्वीकार किए
- बॉन्ड की बिकवाली से स्वीकार किए 6,825 करोड़ रुपये

बॉन्ड डीलरों ने कहा कि छोटी अवधि के बॉन्ड को प्रभावित करने के लिए ओएमओ की जरूरत नहीं है, क्योंकि नकदी के लिए वे इसी बॉन्ड पर निर्भर हैं। डीलरों ने कहा कि इस समय औसत नकदी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये है और अगर इसमें यहां से कमी आती है तो छोटी अवधि के बॉन्ड पर प्रातियां वैसे भी बढ़ जाएंगी। कारोबारियों केअनुसार ज्यादातर बैंकों ने अपनी खुदरा उधारी दर रीपो से जोड़ दी है, जो इस समय 5.15 प्रतिशत है।

हर्ष वर्द्धन श्रींगला होंगे अगले विदेश सचिव

अमेरिका में भारत के राजदूत हर्ष वर्द्धन श्रींगला को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1984 बैच के अधिकारी श्रींगला नए विदेश सचिव के रूप में 29 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे।

झारखंड में हेमंत के सिर जीत का ताज

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 23 दिसंबर

झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही आज केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथ से एक और राज्य निकलना तय हो गया। देर रात तक आए नतीजों और रुझानों ने साफ कर दिया है कि भाजपा की सत्ता से विदाई हो रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की अगुआई वाला गठबंधन नई सरकार बनाएगा। झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का गठबंधन दमदार प्रदर्शन करते हुए 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत हासिल करता दिख रहा है। यह देखकर निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी शाम को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया।

झारखंड : किसको, कितनी सीट
कुल सीट : **81**

पार्टी	जीत	बढ़त	कुल
झाझुमो+	21	26	47
भाजपा	13	12	25
झाविमो	—	3	3
आजसू	2	—	2
अन्य	1	3	4

नोट : झाझुमो+ में कांग्रेस और राजद भी शामिल

देर शाम तक झामुमो गठबंधन 18 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी और 28 पर आगे चल रही थी। सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावों में बड़ा झटका लगा है और वह 26 सीटों पर सिमटती दिख रही है। खबर लिखे जाने तक मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने ही पार्टी के बागी सरयू राय से लगभग 16,000 से भी अधिक मतों से पीछे चल रहे थे। इसके साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनावों में निवर्तमान मुख्यमंत्रियों के हारने का अजीब सिलसिला इस बार भी जारी रहा।

अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अगुआई में झामुमो अकेले 30 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सहयोगी कांग्रेस का भी प्रदर्शन बेहतर रहा है और उसके खाते में 16 सीटें आ रही हैं। गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जल्द ही वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हेमंत ने कहा कि निश्चित तौर पर राज्य के लिए नया अध्याय शुरू होगा और यह राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन को जीत की बधाई दी।

दूसरी ओर भाजपा से गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने वाली आजसू को 2 सीटें मिली हैं। बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) को 3 सीटें मिली हैं। ■ संबंधित खबर : पृष्ठ 14

देश में बचे महज सवा लाख गधे!

चीन में दवा बनाने के लिए दुनिया भर से चुराए जा रहे गधे, भारत के गधों पर भी गिर रही गाज

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 23 दिसंबर

हो सकता है कि आपको अपने आसपास या गली-मुहल्ले में गधे मुश्किल से ही नजर आते हों क्योंकि गधे देश से गायब होते जा रहे हैं। कुछ अरसा पहले जारी 20वीं पशुधन गणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में गधों की संख्या तेजी से घटी है। इसकी मुख्य वजह दूरदराज के इलाकों में छोटी दूरी तक आवागमन या माल ढुलाई के गधों का इस्तेमाल कम होना बताई जा रही है। लेकिन एक वजह पड़ोसी देश चीन को भी बताया जा रहा है, जहां एक खास दवा 'ईच्याओ' बनाने के लिए गधों की खाल का इस्तेमाल होता है।

पशु गणना के अनुसार 2007 से 2012 के बीच देश में गधों की संख्या में 23 फीसदी गिरावट आई और उसके बाद 2012 से 2019 के बीच इनकी आबादी 61.23 फीसदी गिर गई। गणना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब केवल 1.20 लाख गधे ही बचे हैं।

- चीन में ईच्याओ नाम की औषधि बनाने में होता है गधों की खाल का इस्तेमाल
- चीन दुनिया भर से बड़े पैमाने पर मंगाता है गधों की खाल
- 5,600 टन ईच्याओ बनाने में सालाना 48 लाख गधों की खाल की होती है जरूरत
- ईच्याओ के उत्पादन की वृद्धि दर सालाना 20 फीसदी है

ब्रुक इंडिया जैसी पशु कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाएं मानती हैं कि भारत में दुनिया के बाकी हिस्सों की ही तरह गधे कम हो रहे हैं। संस्था के मुताबिक चीन में दवा बनाने के लिए भारत से गधे खरीदे और चुराए जा रहे हैं। 'ईच्याओ' दवा गधों की खाल से बनाई जाती है और इसकी वजह से चीन में भी गधों की संख्या में तेजी से कमी आई है, जिसके बाद ईच्याओ उद्योग अब दूसरे देशों से गधों की खाल मंगाने पर जोर दे रहा है। वैश्विक पशु कल्याण संगठन डंकी सैंक्चुअरी की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है चीन के ईच्याओ उद्योग को सालाना 48 लाख गधों की खाल की जरूरत होती है, जबकि चीन में गधों की संख्या 1992 के 1.1 करोड़ से घटकर महज 26 लाख रह गई है। इसीलिए यह उद्योग दुनिया भर से गधे मंगा रहा है। यही वजह है कि भारत में भी गधे कम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बहुत से कमजोर समुदायों, खासकर पर महिलाओं के लिए गधे गरीबी से बाहर निकलने का जरिया और उनकी आजीविका का साधन हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में पानी लाने और स्वास्थ्य केंद्रों तक लोगों को पहुंचाने तथा बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने में गधे काम आते हैं। गधों पर सामान की ढुलाई भी होती है, जिससे समुदाय की आर्थिक दशा सुधरती है। गधों की खाल के व्यापार से इन समुदायों पर भी गहरा असर पड़ा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय व्यापारी गधों के साथ बहुत क्रूर बर्ताव करते हैं। अक्सर गर्भावस्था के अंतिम चरण में पहुंची गधी, गधे के नन्हे बच्चों और बीमार तथा घायल गधों को बेच दिया जाता है। इन्हें चारा-पानी दिए बगैर ट्रकों में खचाखच भरकर ले जाया जाता है। अक्सर 20 फीसदी गधे बूचड़खानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के गधों से कई तरह की बीमारियां होने और दुनिया भर में संक्रमण फैलने का भी जोखिम रहता है।

खबरों में रहे स्टॉक

नेस्ले इंडिया

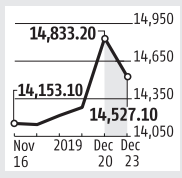

बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में 23 दिसंबर से शामिल

₹ 14,833.20 पिछला बंद भाव
₹ 14,527.10 आज का बंद भाव
▼ 2.06 %

बीएएसएफ इंडिया

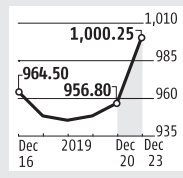

मूल कंपनी की निर्माण रसायन कारोबार के अधिग्रहण की तैयारी

₹ 956.80 पिछला बंद भाव
₹ 1,000.25 आज का बंद भाव
▲ 4.54 %

केईसी इंटरनैशनल

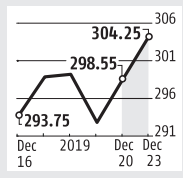

विभिन्न कारोबार को मिले 1,520 करोड़ रुपये के ऑर्डर

₹ 298.55 पिछला बंद भाव
₹ 304.25 आज का बंद भाव
▲ 1.91 %

क्रिसिल

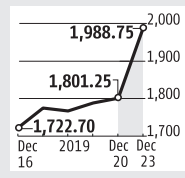

एसऐंडपी बीएसई में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 1,801.25 पिछला बंद भाव
₹ 1,988.75 आज का बंद भाव
▲ 10.41 %

रिलायंस इंडस्ट्रीज

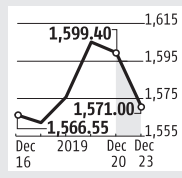

सउदी अरामको सौदे पर सरकार ने लगाई रोक

₹ 1,599.40 पिछला बंद भाव
₹ 1,571.00 आज का बंद भाव
▼ 1.78 %

संक्षेप में

रिलायंस इन्फ्रा ने जीता मध्यस्थता मुकदमा

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि इस राशि का इस्तेमाल ऋणदाताओं का भुगतान करने और कंपनी का कर्ज कम करने के लिए किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने शनिवार को सर्वसम्मति से रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला दिया। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पश्चिम बंगाल में डीवीसी की 1,200 मेगावॉट की रघुनाथपुर ताप बिजली परियोजना का इंजीनियरिंग और निर्माण अनुबंध मिला था। कंपनी ने कहा है कि उसने भारत सरकार के उपक्रम डीवीसी के खिलाफ एक बड़ा 1,250 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मुकदमा जीत लिया है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने डीवीसी को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को 896 करोड़ रुपये का भुगतान करने और 354 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी चार सप्ताह में लौटाने को कहा है। भुगतान में चार सप्ताह से अधिक लगने पर डीवीसी को 15 फीसदी दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा। *भाषा*

लोन स्टार की संबद्ध इकाई करेगी अधिग्रहण

वैश्विक निजी इक्विटी कंपनी लोन स्टार की संबद्ध इकाई बीएएसएफ के निर्माण रसायन कारोबार का 3.17 अरब यूरो या करीब 25,003 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करेगी। बीएएसएफ ने लोन स्टार की संबद्ध कंपनी के साथ अपना निर्माण कारोबार बेचने के लिए करार किया है। बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में बीएएसएफ लि. ने कहा, 'हमें मूल कंपनी बीएएसएफ एसई, जर्मनी की ओर से सूचित किया गया है कि उसने लोन स्टार की संबद्ध कंपनी के साथ बीएएसएफ के निर्माण रसायन कारोबार को बेचने के लिए करार किया है।' कंपनी ने कहा कि यह सौदा नकद और ऋण मुक्त होगा। सौदे का मूल्य 3.17 अरब यूरो बैठेगा। यह सौदा 2020 की तीसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए सक्षम प्राधिकरणों की मंजूरी ली जाएगी। *भाषा*

ओएनजीसी के नियंत्रण में पीएमटी

पन्ना, मुक्ता एवं ताप्ती का नियंत्रण आरआईएल एवं शेल से अब ओएनजीसी के पास

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 23 दिसंबर

पन्ना-मुक्ता एवं ताप्ती (पीएमटी) क्षेत्रों से 4.5 अरब डॉलर के मुनाफा एवं रॉयल्टी के सरकार के दावे को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के बीच सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) एवं शेल से उन क्षेत्रों का नियंत्रण हासिल कर लिया है। सरकार ने सऊदी अरामको के साथ 15 अरब डॉलर के सौदे सहित आरआईएल की हिस्सेदारी बिक्री योजनाओं पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया था।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचाट के फैसले के तहत पीएमटी के लिए 4.5 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने सरकार के दावे का खंडन किया था। सूत्रों के अनुसार, मध्यस्था प्रक्रिया का अंतिम चरण 2020 के मध्य में निर्धारित है और सरकार ने एकतरफा गणना के आधार जिस रकम का दावा किया है उस पर भी विवाद है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरआईएल से कहा था कि वह अपनी परिसंपत्तियों का खुलासा करे। इसका मतलब साफ है कंपनी को 20 फीसदी हिस्सेदारी सउदी अरामको को बेचने से पहले अपनी सभी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध कराना होगा। सरकार का दावा ब्रिटेन की अदालत के 2016 के फैसले पर आधारित है जिसमें रकम का उल्लेख नहीं किया गया है। कंपनियों का मानना है कि जब तक ट्रिब्यूनल रकम को निर्धारित नहीं करेगा तक तक मौजूदा स्थिति में कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है।

पीएमटी को लेकर जारी कानूनी लड़ाई के बावजूद शनिवार की रात उसका नियंत्रण ओएनजीसी को सौंप दिया गया। इस मामले के एक करीबी सूत्र ने कहा, 'इस कानूनी लड़ाई से पीएमटी पर नियंत्रण का हस्तांतरण प्रभावित नहीं होगा क्योंकि आरआईएल और शेल दोनों इन ब्लॉकों को लौटा रही हैं। वे उन ब्लॉकों को बेच नहीं रही हैं। कुल मिलाकर सरकार की मनोनीत कंपनी उन परिसंपत्तियों को हासिल कर रही हैं।' अदालत का यह निर्देश पिछले सप्ताह हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आया।

एक सूत्र ने कहा कि मध्यस्थता ट्रिब्यूनल उत्पादन साझेदारी अनुबंध के तहत लागत वसूली सीमा में बढ़ोतरी के संदर्भ में आरआईएल और शेल की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। इस मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला यदि उनके पक्ष में रहा तो सरकार के दावे में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

सरकार ने ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत भुगतान के लिए कंपनी की क्षमता के बारे में चिंता जताई थी क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए उत्पादन साझेदारी अनुबंध की समय-सीमा 21 दिसंबर को खत्म हो चुकी है। आरआईएल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति दमदार है। पन्ना-मुक्ता एवं ताप्ती संयुक्त उद्यम में आरआईएल और शेल दोनों की 30-30 फीसदी हिस्सेदारी थी। जबकि शेष 40 फीसदी हिस्सेदारी ओएनजीसी के पास थी।

कानूनी जंग के बीच नियंत्रण हस्तांतरण

- सरकार का 4.5 अरब डॉलर के मुनाफा एवं रॉयल्टी का दावा, कानूनी जंग जारी
- मध्यस्थता पंचाट के फैसले के तहत पीएमटी के लिए नहीं किया गया भुगतान

डेबिट कार्ड की संख्या में आई गिरावट

निधि राय
मुंबई, 23 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2019 में डेबिट कार्ड की संख्या 15 फीसदी घटकर 2 साल के निचले स्तर पर आ गई। साल 2018 में डेबिट कार्ड की संख्या 99.8 करोड़ थी जो घटकर 2019 में 84.3 करोड़ रह गई।

बैंकरों का मानना है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप से चिप आधारित डेबिट कार्ड के लिए ईवीएम (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीजा) माइग्रेशन पर आरबीआई के निर्देश के कारण ऐसा हुआ होगा। इसके कारण करीब 15.5 करोड़ कार्ड बाजार से बाहर हो गए। साल 2018 में बैंकों ने डेबिट कार्ड के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए और निष्क्रीय कार्डों को बाहर किया।

फेडरल बैंक के निदेशक आशुतोष खजूरिया ने कहा, 'हमारे बैंक में दिख रहा है कि बड़ी तादाद में ग्राहकों ने यूपीआई एवं अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया है। इसे पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) और एटीएम पर कार्ड के उपयोग में गिरावट आई है।' बैंकों ने भी उन ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करना बंद कर दिया है जो उसके लिए आग्रह नहीं करते हैं। वित्तीय सेवा प्रदाता एफआईएस ग्लोबल के सीआरओ भरत पंचाल ने कहा कि बैंक निष्क्रिय खातों के लिए डेबिट कार्ड जारी न करते हुए पैसे बचा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'किसी बैंक के लिए निष्क्रीय खाते को बरकरार रखना व्यवहार्य नहीं है। इसके दो कारण हैं- पहला, काले धन को सफेद करने आदि धोखाधड़ी को जोखिम होता है और दूसरा, इस प्रकार के खाते को बरकरार रखने की लागत होती है। इसलिए बैंकों ने ग्राहकों द्वारा संपर्क किए बिना कार्ड जारी करना बंद कर दिया है।'

निष्क्रिय खातों की एक बड़ी वजह शहरी भारतीयों द्वारा लगातार नौकरी बदलना है। वे पिछले रोजगार के दौरान खुलवाए गए खातों को बंद नहीं कराते और नए वेतन खाते खुलने के बाद धीरे-धीरे उसका उपयोग कम होता जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जन धन खातों के जरिये रूपे डेबिट कार्ड की उपयोगिता बढ़ने से भी डेबिट कार्ड को झटका लगा है। रूपे कार्ड की संख्या नवंबर 2019 में सालाना आधार पर 13.5 फीसदी की वृद्धि के साथ 29.68 करोड़ हो गई।

संगीता रेड्डी फिक्की की अध्यक्ष, उदय शंकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष

अपोलो हॉस्पिटल समूह की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने देश के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। वह 2019-20 के लिये अध्यक्ष चुनी गई हैं। संगीता रेड्डी एसआईएल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप सोमानी की जगह फिक्की की अध्यक्ष बनी हैं। फिक्की की विज्ञप्ति के अनुसार वाल्ट डिजनी कंपनी एपीएसी के अध्यक्ष और स्टार ऐंड डिजनी इंडिया चेयरमैन उदय शंकर अब फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे, जबकि हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फिक्की का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। रेड्डी ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है, 'मैं फिक्की और देश के लिये आने वाले वर्ष के बहुत ही खास रहने की उम्मीद कर रही हूं। हमारी 92वीं वार्षिक आम बैठक में हमने भारत के लिये 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिये कार्ययोजना का खाका तैयार किया है। पिछले सप्ताहांत समाप्त हुई हमारी इस वार्षिक आम बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। *भाषा*

होमलेन ने पिडिलाइट व अन्य से जुटाई रकम

युवराज मलिक
बेंगलूरु, 23 दिसंबर

वेब-समर्थ इंटीरियर डिजाइन फर्म होमलेन ने डी श्रृंखला के वित्त पोषण के तहत इवॉल्वेंस इंडिया, पिडिलाइट ग्रुप और एफजे लैब्स से 3 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इवॉल्वेंस दुबई का फंड ऑफ फंड्स है जिसकी कुछ भारतीय निजी इक्विटी कंपनियों में निवेश है। पिडिलाइट एक सूचीबद्ध एवं औद्योगिक रसायन बनाने वाली कंपनी है जबकि एफजे लैब्स फाइंड और जूमकार की निवेशक कंपनी है। इस फंड की स्थापना ओएलएक्स के संस्थापक फैबराइस ग्रिंडा ने की थी।

होमलेन के मौजूदा निवेशकों में सिकोया कैपिटल, ऐक्सेल पार्टनर्स और जेएसडब्ल्यू वेंचर्स ने भी ताजा दौर के निवेश में भाग लिया। इस प्रकार पांच साल पुराने इस स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई कुल रकम 4.6 करोड़ डॉलर हो गई। इंटीरियर डिजाइनिंग आमतौर पर एक ऑफलाइन कारोबार रहा है। लेकिन होमलेन और उसकी प्रतिस्पर्धी लिवस्पेस ने डिजाइनरों, पेंट एवं अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराने वालों और ग्राहकों को इंटरनेट पर एकसाथ लाया है।

लेमन ट्री के शेयर में बढ़त के आसार

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 23 दिसंबर

गोवा में लाइसेंसिंग सौदा और विदेशी बाजारों में विस्तार की घोषणा के बाद पिछले दो कारोबारी सत्रों में लेमन ट्री होटल्स के शेयर में 7 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। गोवा में 44 कमरों की संपत्ति के लिए प्रबंधन अनुबंध के साथ ही कंपनी ने राज्य में अपनी पांचवीं संपत्ति जोड़ी जिससे उसके कमरों की संख्या बढ़कर 379 हो गई है।

लेमन ट्री ने दुबई में 114 कमरों की संपत्ति के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दस्तक दी है। ये दोनों अनुबंध होटलों के संचालन के लिए प्रबंधन करार हैं जो संपत्ति हल्का करने संबंधी कंपनी की रणनीति के अनुरूप हैं। इससे कंपनी को वृद्धि के मोर्चे पर अपनी रफ्तार बढ़ाने, परिचालन मुनाफा मार्जिन को सुधारने और बहीखाते को हल्का करने में मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 2015 से 2019 की अवधि में कंपनी की कुल इन्वेंटरी में 16 फीसदी की वृद्धि हुई जबकि प्रबंधन वाले होटल कमरों की संख्या में 61 फीसदी की वृद्धि हुई। कंपनी के 5,800 से अधिक (प्रमुख अधिग्रहण को छोड़कर) कमरे प्रबंधित होटलों के हैं।

बिक्री को रफ्तार देने वाले कारकों में मांग में तेजी और नए होटल कमरों का आधिग्रहण शामिल हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2022 के अंत तक लेमन ट्री के कमरों की संख्या बढ़कर 10,000 से अधिक हो जाएगी। घरेलू आतिथ्य सेवा उद्योग में तेजी और होटल कमरों की भराव दर 65 फीसदी के पार होने से वृद्धि को रफ्तार मिलेगी।

आईडीबीआई कैपिटल की अर्चना गुडे और साहिल विज का मानना है कि आतिथ्य सेवा उद्योग को घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति की सकारात्मक स्थिति से फायदा होगा। ऐसे में लेमन ट्री जैसी प्रमुख कंपनियों को सबसे अधिक फायदा होगा क्योंकि मझोले बाजार श्रेणी में उसकी बाजार हिस्सेदारी 16 फीसदी है। विभिन्न श्रेणियों के साथ-साथ प्रमुख बाजारों में कंपनी मौजूदगी बढ़ने से उसकी बिक्री को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

विश्लेषकों ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2022 तक कंपनी की बिक्री करीब दोगुना होकर 935 करोड़ रुपये हो जाएगी। होटलों में कमरों के भराव और औसत किराये में उल्लेखनीय वृद्धि से बिक्री की रफ्तार बढ़ेगी।

मौजूदा मूल्य पर कंपनी का शेयर वित्त वर्ष 2021 के अनुमान के मुकाबले 44 गुना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। इसमें नरमी आने पर निवेशक लिवाली कर सकते हैं।

मजबूत बढ़त

वर्ष	कमरों की संख्या	शुद्ध बिक्री (करोड़ रुपये)
वित्त वर्ष 2019	5,411	549
वित्त वर्ष 2020 (अनुमानित)	8,381	754
वित्त वर्ष 2021 (अनुमानित)	9,644	826
वित्त वर्ष 2022 (अनुमानित)	10,379	953

स्रोत : कंपनी, आईडीबीआई कैपिटल

बीपीसीएल की कार्य संस्कृति आकर्षक

अमृता पिल्लई
मुंबई, 23 दिसंबर

वर्ष 2016 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 1976 के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) राष्ट्रीयकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया तो कभी निजी कंपनी रह चुकी बीपीसीएल के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हालांकि कंपनी के पूर्व एवं मौजूदा कर्मचारियों और उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीयकरण के बावजूद बीपीसीएल ने विदेशी एवं निजी कंपनियों की तरह अपनी कार्य संस्कृति को बरकरार रखा।

बीपीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, 'बीपीसीएल को हमेशा से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर देखा गया जबकि यह एक सरकारी कंपनी है। इससे पता चलता है कि हमारी कार्य संस्कृति दूसरों के मुकाबले कितना अलग है।'

बीपीसीएल का सफर बर्मा ऑयल कंपनी से शुरू होकर बर्मा-शेल और फिर राष्ट्रीयकरण के बाद मौजूदा बीपीसीएल तक की है। इस कंपनी की शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई थी जो दक्षिण एशियाई बाजारों से होकर 1950 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अपना ठौर बनाया जब उसने मुंबई के ट्रॉम्बे में एक आधुनिक रिफाइनरी का निर्माण किया था। बाद में 1976 में बर्मा शेल के राष्ट्रीयकरण से मौजूदा बीपीसीएल के लिए रास्ता साफ हुआ।

समझा जाता है कि बीपीसीएल के राष्ट्रीयकरण का मुख्य कारण 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था।

केंद्र सरकार ने 20 नवंबर को बीपीसीएल में अपनी पूरी 53.29 फीसदी हिस्सेदारी को बेचने और उसके प्रबंधन पर अपना नियंत्रण एक रणनीतिक खरीदार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस मामले से अवगत लोगों का कहना है कि इसने कई विदेशी बोलीदाताओं को आकर्षित किया है और उनमें से अधिकतर तेल उत्पादक कंपनियां हैं जो अपने उत्पाद के लिए बाजार सुरक्षित करना चाहती हैं। जहां तक विदेशी अथवा निजी निवेशकों का सवाल है तो उन्हें राष्ट्रीयकरण से पहले की इसकी कार्य संस्कृति को लेकर संभवत: कोई समस्या नहीं होगी। कुछ लोगों का मानना है कि बीपीसीएल ने अपने राष्ट्रीयकरण से पहले की कार्य संस्कृति को अच्छी तरह बचाकर रखा है।

- बीपीसीएल की कार्य संस्कृति से आकर्षित होंगे नए निवेशक
- राष्ट्रीयकरण के बावजूद कंपनी ने अपनी कार्य संस्कृति को विदेशी एवं निजी कंपनियों की तरह बरकरार रखा

बीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सार्थक बेहरा ने कहा, 'राष्ट्रीयकरण के बावजूद बर्मा शेल वाली कार्य संस्कृति बरकरार रही। बर्मा शेल के तमाम कर्मचारी बीपीसीएल में बने रहे और नए कर्मचारियों को उसी संस्कृति में प्रशिक्षित किया गया। निर्णय लेने के मोर्चे पर कंपनी दूसरों से अलग थी। वह संकट प्रबंधन में कहीं अधिक पेशेवर और त्वरित प्रतिक्रिया देती थी।' बेहरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक पी एलंगो ने कहा कि बीपीसीएल के कार्यालयों में अधिकारियों के नेमप्लेट लगाने का चलन नहीं है जो इस संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, 'निदेशकों और सहायकों के लिए वहां कोई नेमप्लेट नहीं है और एक-दूसरे को नाम से बुलाने की संस्कृति है।'

सांख्यिकी आयोग की ताकत घटाने की तैयारी

प्रस्तावित कानून में निकाय को आधिकारिक सर्वेक्षण रिपोर्टों को मंजूरी देने,जारी करने की शक्ति नहीं

सोमेश झा
नई दिल्ली, 23 दिसंबर

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) पर प्रस्तावित कानून में आधिकारिक आंकड़ों की स्वायत्तता के लिए जरूरी एक महत्त्वपूर्ण बिंदु को छोड़ दिया गया है। इसमें इस निकाय को आधिकारिक सर्वेक्षण रिपोर्टों को मंजूरी देने और जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है।

एनएससी विधेयक के मसौदे को पिछले हफ्ते सार्वजनिक करते हुए इस पर राय मांगी गई थी। इस मसौदे में एनएससी को विभिन्न स्तरों पर आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली की आवधिक समीक्षा के संदर्भ में एक सलाहकार की भूमिका दी गई है। मसौदे को जारी करते हुए सरकार ने कहा कि उसने इसका विचार 2000-01 में बने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अगुआई वाले आयोग से लिया है।

हालांकि, रंगराजन आयोग ने देश की सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों के लिए एनएससी को एक नोडल और सशक्त निकाय बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने कहा कि एनएससी एक नोडल सशक्त निकाय होगा जिसके जिम्मे ऐसे आंकडों के सेटों के लिए आवश्यक मानकों की स्थापना करने का काम होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक एनएससी की स्थापना 2005 में ही की गई थी लेकिन उसके पास विधायी ढांचा नहीं होने के कारण उसे अपनी सिफारिशों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

एनएससी को कॉर्पोरेट निकाय के तौर पर स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें पूर्णकालिक सदस्य होंगे जबकि फिलहाल इसमें अंशकालिक सदस्य हैं। एनएससी के एक पूर्व चेयरमैन ने कहा कि यह सारी कवायद एनएससी को थोड़ी स्वायत्तता देने की दिशा में एक कदम आगे ले जाएगा।

हालांकि, चेयरमैन सहित एनएससी के सभी सदस्यों के रैंक की बात कानून के मसौदे में नहीं है। मसौदा अधिनियम के मुताबिक एनएससी सरकार का हिस्सा होने नहीं जा रहा है क्योंकि इसे एक निकाय के तौर पर गठित किया जाएगा। पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् और एनएससी के चेयरमैन रह चुके प्रणव सेन ने कहा कि एनएससी सदस्यों के रैंक और प्रतिष्ठा के बारे में कोई चर्चा नहीं होने से निकाय का कद धुमिल होता है। फिलहाल एनएससी के चेयरमैन का दर्जा राज्यमंत्री के बराबर होता है वहीं एनएससी के सभी सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। सेन ने कहा कि चूंकि किसी बाहरी एजेंसी को आधिकारिक आंकड़ों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है लिहाजा इसे सलाहकार की भूमिका दी गई है।

हालांकि, एनएससी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सर्वेक्षण रिपोर्टों को मंजूरी देने के अंतिम प्राधिकरण बनाने को कोई जिक्र नहीं किया गया है। सरकार की यह कवायद ऐसे समय पर सामने आ रही है जब उसने एनएसओ सर्वेक्षण की रिपोर्टों को जारी करने से रोक लिया था।

मसौदा विधेयक के मुताबिक आयोग ऐसी एजेंसियों की पहचान करेगा जो प्रमुख आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन तथा आंकड़ों के कैलेंडर जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य सांख्यिकीविद् प्रवीण श्रीवास्तव ने बिजनेस स्टैंडर्ड के प्रश्नों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की कुछ शक्तियां और कार्य

- केंद्र और राज्य सरकारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर सुझाव देना
- आधिकारिक आंकडों से जुड़े विधायी उपाय
- आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्रमुखताओं की पहचान और विकास
- आधिकारिक आंकड़ों के लिए मानक सांख्यिकीय अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण और कार्य पद्धति तैयार करना
- सांख्यिकी पेशे के लिए लोकाचार हेतु उच्च पेशेवर मानकों की स्थापना और आचार संहिता तैयार करना
- प्रमुख आंकड़ों का संग्रह, संकलन और प्रसारण
- आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन तथा आंकडों का कैलेंडर जारी करने के लिए एजेंसियों की पहचान

रात में विमानों की पार्किंग के लिए छोटे शहरों की वकालत

अनीश फडणीस
मुंबई, 23 दिसंबर

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) चाहती है कि एयरलाइंस अपने ज्यादा विमानों की रात में पार्किंग गैर मेट्रो शहरों में करें, क्योंकि उसके अधीन आने वाले प्रमुख हवाईअड्डों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है और उनके विस्तार की बहुत सीमित संभावना है।

अगले 5 साल में भारत में विमानन कंपनियों के बेड़े का आकार 1,200 से ज्यादा विमानों का हो सकता है और भारत एक दशक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार बनने की ओर है। बेंगलूरु और दिल्ली (तीसरा सबसे व्यस्त और भारत का सबसे व्यस्त हवाईअड्डा) में जहां दो नए टर्मिनल होंगे और एयरलाइंस के लिए 2021 तक करीब 60 अतिरिक्त पार्किंग बे बन जाएंगे, वहीं एएआई द्वारा संचालित बड़े हवाईअड्डों चेन्नई, गोवा और पुणे (10 व्यस्त हवाईअड्डों में से एक) में विस्तार की संभावना नजर नहीं आती क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं है।

हाल की बैठक में एएआई ने एयरलाइंस से कहा था कि व्यस्त हवाईअड्डों की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए वे टियर-2 और टियर-3 शहरों में विमानों की रातभर की पार्किंग पर विचार करें। इस समय कोलकाता में रात को पार्किंग के लिए एक भी खाली बे नहीं है, जबकि चेन्नई में कुछ जगहें बची हैं। यहां पर टर्मिनल नहीं बन सकते, ऐसे में परिचालन को लेकर असुविधा हो रही है। निजी हवाईअड्डों में जहां बेंगलूरु और हैदराबाद में 2020 से पार्किंग सुविधा बढ़ाई जा रही है, दिल्ली और मुंबई में विमानों की रात की पार्किंग के लिए जगह शेष नहीं है।

एएआई के एक अधिकारी ने कहा कि अबसे 2022 तक 20 हवाईअड्डों पर करीब 360 बे जोड़े जाएंगे। प्राधिकरण औरंगाबाद, भुवनेश्वर, इंदौर, गुवाहाटी, मंगलूर, मदुरै के अलावा अन्य जगहों पर बुनियादी ढांचे का उन्नयन कर रहा है। उसने एयरलाइंस को सुझाव दिया है कि वे चंडीगढ़ को आधार बनाएं, जहां कुहरे की स्थिति में भी उड़ान की सुविधा है।

एएआई के पश्चिमी क्षेत्र ने भी मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में एविएशन टर्बाइन पर मूल्यवर्धित कर घटाए, जिससे वहां विमानों की रात में पार्किंग को प्रोत्साहित किया जा सके। इस तरह की पहल पिछले साल तमिलनाडु ने की थी और कोयंबटूर हवाईअड्डे पर एटीएफ पर कर घटा दिया था, जिसकी वजह से इंडिगो और जेट एयरवेज ने वहां विमानों की पार्किंग शुरू कर दी।

वहीं विमान कंपनियों ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में यात्रियों की संख्या कम होने को लेकर चिंता जताई और कहा कि इससे लागत में बढ़ोतरी होगी। एक निजी विमान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'पायलटों व क्रू के रहने की वव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग और सुरक्षा से जुड़ी अतिरिक्त लागत पर विचार करते हुए एक एयरलाइंस ेक कम से कम 4 विमान टियर-2 या टियर-3 शहरों के हवाईअड्डों पर खड़े करने होंगे।' एयरलाइंस ने यह भी कहा कि छोटे शहरों में परिचालन के घंटे सीमित हैं और इन्हें हर वक्त उड़ान के लिए खोले जाने की जरूरत है।

एविएशन ब्लॉग नेटवर्क थॉट्स चलाने वाले अमेय जोशी ने कहा, 'पिछले कुछ साल से एयरलाइंस ने छोटे शहरों जैसे इंदौर, नागपुर, कोयंबटूर, पटना और अन्य हवाईअड्डों पर रात को पार्किंग शुरू कर दी है। आने वाले महीनों में एयरलाइंस को और विमान छोटे शहरों में खड़े करने होंगे, लेकिन यह बेड़े पर निर्भर होगा। 2020 में बेड़े में नए विमान जोड़ा जाना इस बात पर निर्भर होगा कि कितनी जल्दी बोइंग 737 मैक्स आसमान में लौटता है और कब ए320नियो इंजन से जुड़े मसले का समाधान कर लिया जाता है।'

विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइंस के पास मार्च 2020 तक 42 विमान होंगे। कंपनी ने ए320 और बोईंग787 सहित 56 विमानों का ऑर्डर दिया है और ये विमान अगले 4 साल में बेड़े में शामिल हो जाएंगे।

इंडिगो ने कहा कि दीर्घावधि जरूरतों को देखते हुए वह एयरपोर्टों व एएआई से लगातार संपर्क में है और उसे भरोसा है कि उनकी वृद्धि योजना में पर्याप्त बुनियादी ढांचा विकसित किया जाना शामिल है। इंडिगो ने कहा, 'एयरलाइंस मेट्रो व नॉन मेट्रो दोनों ही शहरों में पार्किंग बे का इस्तेमाल करती है और उसकी सीजनल शेड्यूल डेवलपमेंट प्रक्रिया में बे की उपलब्धता को देखते हुए अहम डिजाइन तैयार की जाती है, जिससे सभी वक्त तालमेल बिठाया जा सके।'

बढ़ती भीड़ से संकट

- उड्डयन सलाहकार सीएपीए ने फरवरी में अनुमान लगाया था कि **2024** तक होंगे **1199** विमान
- इसमें **1060** नैरो बॉडी प्लेन और **133** वाइड बॉडी प्लेन शामिल होंगे
- अब से **2022** तक **20** हवाईअड्डों पर करीब **360** बे जोड़े जाएंगे
- एएआई ने राज्यों से कहा है कि वे एटीएफ पर शुल्क कम करें, जिससे छोटे शहरों में विमानों की रात को पार्किंग को बढ़ावा मिल सके
- एयलाइंस ने टियर-2 शहरों में यात्रियों की सीमित मांग को लेकर जताई चिंता

ओडिशा में बिजली पहुंचाएगी टाटा

अमृता पिल्लई
मुंबई, 23 दिसंबर

टाटा पावर ने आज कहा है कि उसे ओडिशा के 5 सर्किल में बिजली वितरण लाइसेंस का आशय पत्र (एलओआई) मिल गया है। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 साल में अपना बिजली वितरण कारोबार बढ़ाकर 4 गुना करना है।

कंपनी ने एक बयान में कहा है, 'ओडिशा बिजली नियामक आयोग (ओईआरसी) ने टाटा पावर कंपनी को एलओआई आवंटित किया है और कंपनी की सफल बोलीदाता के रूप में चयन की सूचना दी है। कंपनी को ओडिशा के 5 सर्किल में बिजली की खुदरा आपूर्ति और वितरण का लाइसेंस मिल गया है।'

यह पांच केंद्र सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई युटिलिटी आफ ओडिशा (सीईएसयू) के तहत आते हैं।

इन 5 सर्किल से टाटा पावर के मुंबई, दिल्ली और अजमेर के 25 लाख उपभोक्ताओं में 25 लाख नए उपभोक्ता और जुड़ जाएंगे। चाचा पावल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीर सिन्हा ने कहा, 'हम अगले 3 साल में ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर 1 करोड़ करने पर काम कर रहे हैं।'

टाटा पावर ने बयान में कहा है, 'सीईएसयू की टाटा पावर को प्रस्तावित बिक्री विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) के गठन के माध्यम से होगी।' टाटा पावर की इस एसपीवी में इक्विटी 51 प्रतिशत होगी, जबकि ओडिशा सरकार की शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

सिन्हा ने कहा कि कंपनी ओडिशा के अन्य लाइसेंसों का भी मूल्यांकन करेगी कि वे कब बोली के लिए आएंगे। उन्होंने कहा, 'उनके भी सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी पर आने की उम्मीद है और हम इसी तरह के और मौके पर विचार कर रहे हैं।' ओडिशा के बाहर भी कंपनी वितरण के मौकों की तलाश कर रही है। सिन्हा ने कहा, 'हम उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कुछ राज्यों में भी अवसर तलाश रहे हैं। बोली प्रक्रिया शुरू होने पर हम उसमें शामिल होंगे।'

टाटा पावर अपने उपभोक्ता आधार बढ़ाकर 4 गुना करने की रणनीति बना रही है। सिन्हा को उम्मीद है कि टाटा पावर की वित्तीय स्थिति में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।

30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में पारेषण और वितरण कारोबार की इस क्षेत्र के कु ल 7,315.43 करोड़ रुपये राजस्व में हिस्सेदारी 3,207.63 करोड़ रुपये थी।

- पांच बिजली सर्किल भुवनेश्वर (इलेक्ट्रिकल सर्किल 1 और 2) कटक, पारादीप और ढेकनाल टाटा को मिले
- इन क्षेत्रों में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि करीब 30 प्रतिशत
- शुरुआत में टाटा पावर को 25 साल के लाइसेंस की पेशकश
- इसके लिए बने संयुक्त उपक्रम में टाटा की 51 प्रतिशत और ओडिशा सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी
- टाटा का लक्ष्य अगले 3 साल में अपना बिजली वितरण कारोबार बढ़ाकर 4 गुना करना

ओला ने 17 शहरों में पेश किया कृत्रिम मेधा सक्षम सुरक्षा फीचर

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 23 दिसंबर

टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ओला ने घोषणा की है कि उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के 17 बाजारों में कृत्रिम मेधा (एआई) सक्षम सुरक्षा फीचर्स गार्जियन पेश किए हैं। भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के कुछ शहरों में प्रायोगिक आधार पर इसके सफल परीक्षण के बाद बेंगलूरु की कंपनी ओला ने कहा कि गार्जियन फीचर भारत के 16 शहरों सहित ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में पेश कर दिया गया है। सॉफ्टबैंक समर्थित कंपनी का लक्ष्य आने वाली तिमाही में गार्जियन फीचर को और शहरों में भी शुरू करने की योजना है।

ओला द्वारा विकसित गार्जियन फीचर विश्व का पहली ऐसी सुविधा है, जिसमें सवारियों से स्वत: रियल टाइम डेटा लिया जाता है, जिससे लंबे इंतजार और मार्ग में अनपेक्षित बदलाव सहित अनियमित ट्रिप गतिविधियों की जानकारी मिल सके। यह अलर्ट ओला की 24 घंटे काम करने वाली सेफ्टी रिस्पॉस टीम को तत्काल मिलेगी, जो ग्राहकों व चालकों से संपर्क साधेंगे कि क्या वे सुरक्षित हैं और यात्रा पूरी होने तक कॉल पर कोई सहयोग देने को तैयार रहेंगे। ग्राहक भी इसके माध्यम से ऐप में आपातकालीन बटन दबाकर अपने परिजनों और पुलिस को आपात स्थिति में सूचना दे सकेंगे। ओला गार्जियन एआई और मशीन लर्निंग क्षमताओं पर आधारित है, जिसमें हर रोज लाखों की संख्या में डेटा के बारे में जानकारी मिल सकेगी और इससे जोखिम के संकेत और तत्काल उसके समाधान की सहूलियत मिलेगी।

> ओला ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के 17 बाजारों में कृत्रिम मेधा सक्षम सुरक्षा फीचर गार्जियन पेश किए

ओला के मार्केटिंग ऑफिसर और बिक्री प्रमुख अरुण श्रीनिवास ने कहा, 'हम नवोन्मेश के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सिससे ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन्हें बेहतर अनुभव मिल सके। गार्जियन में कृत्रिम मेधा को लाया गया है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप भी शामिल है। इससे सभी बाजारों में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी।'

संक्षेप में

भारत पहुंचा 790 टन आयातित प्याज

आयातित प्याज की 790 टन की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसमें से कुछ प्याज दिल्ली और आंध्र प्रदेश भेजा गया है। इन राज्यों को प्याज बंदरगाह पर पहुंचने की लागत 57-60 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर भेजा गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 12,000 टन और प्याज की खेप दिसंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। *भाषा*

कोल इंडिया ने शुरू की कोयला खरीद

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने ओडिशा कोल ऐंड पावर लिमिटेड (ओसीपीएल) की निजी उपयोग वाली मनोहरपुर खदान से 6,000 टन प्रतिदिन कोयले की खरीद शुरू कर दी है। ओसीपीएल ओडिशा सरकार की कंपनी है। *भाषा*

भारत में बढ़ती रोबोटिक सर्जरी पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर

सोहिनी दास
मुंबई, 23 दिसंबर

भारत में रोबोटिक सर्जरी तेजी से जगह बना रही है, जिसे देखते हुए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी नई तकनीक यहां लाने की योजना बना रही हैं।

इस क्षेत्र के विश्लेषकों का कहना है कि यह बाजार 2016 मे 12.99 करोड़ डॉलर का था और 2025 में इसका बाजार 37.25 करोड़ डॉलर (करीब 2,600 करोड़ रुपये) का हो जाएगा और इस क्षेत्र की चक्रवृद्धि वृद्धि दर 19.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। भारत में मेडिकल उपकरण की वृद्धि दर सालाना 28 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो 2025 तक बढ़कर 50 अरब डॉलर (3.6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

उद्योग का दावा है कि करीब 39 भारतीय हेल्थकेयर सुविधाओं में उच्च श्रेणी की रोबोटिक सर्जरी हो रही है। इनमें राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थकेयर, मेदांता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हॉस्पिटल्स, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और जसलोक हॉस्पिटल शामिल हैं।

जॉनसन ऐंड जॉनसन मेडिकल डिवाइस कंपनीज (जेजेएमडीसी) का कहना है कि उसका प्लेटफॉर्म इस समय भारत में मौजूद नहीं है, लेकिन वह वैश्विक नवोन्मेश यहां लाने के लिए काम कर रही है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'इसका एक उदाहरण को क्रियेटेड डिजिटल इको सिस्टम है, जिसका नेतृत्व डीपुई सिंथेस (जेजेएमडीसी की एक इकाई) कर रही है, जो मरीजों के लिए समग्र नी ऑर्थोप्लास्टी की सुविधा मुहैया कराती है।'

बढ़ है रही रोबोटिक सर्जरी

- करीब **39** भारतीय अस्पतालों में हो रही है उच्च श्रेणी की रोबोटिक सर्जरी
- रोबोटिक बाजार 2016 मे **12.99** करोड़ डॉलर का था और 2025 में **37.25** करोड़ डॉलर का हो जाएगा
- स्ट्राइकर, मेडट्रॉनिक्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले रही हैं भारत में नई तकनीक लाने में दिलचस्पी

अक्टूबर में ब्रिटेन की सीएमआर सर्जिकल्स ने अपना पहला वर्सियस रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पुणे के एक अस्पताल को बेचा। इसका प्राथमिक रूप से इस्तेमाल लैप्रोस्कोपिक या मिनिमली इनवेसिव सर्जरी में होता है। यह फर्म सर्जिकल रोबोटिक व्यवस्था के लिए दुनिया की पहली क्लीनिकल रजिस्ट्रीय पेश करने जा रही है।

अमेरिका की इंट्यूटिव सर्जिकल इंक भारत में तेजी से बढ़ती रोबोटिक सर्जरी सिस्टम कंपनी है। कंपनी के जनरल मैनेजर मंदीप सिंह कुमार कहते हैं, 'भारत में रोबोटिक सर्जिकल मार्केट शुरुआती चरण में है, जिसे अभी परिपक्व होना बाकी है। दीर्घावधि के हिसाब से भारत अहम बाजार है।'

कुमार ने कहा, 'भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए हमने प्रशिक्षण केंद्रों पर निवेश किया है, कर्मचारी रखे हैं, जिसमें वह टीम शामिल है, जो सर्जन के साथ काम करती है। साथ ही हम दीर्घावधि के हिसाब से अस्पतालों को मदद कर रहे हैं। हमने हाल में अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं। हमारा लक्ष्य सर्जनों को इस तकनीक का प्रशिक्षण और इस सिलसिले में समर्थन देना है।'

अस्पतालों का कहना है कि एक बार जब बीमा कंपनियां रोबोटिक सर्जरी को कवर करना शुरू कर देंगी, मांग बहुत तेजी से बढ़ सकती है। मणिपाल एजुकेशन ऐंड मेडिकल ग्रुप के चेयरमैन रंजन पई ने कहा, 'भारत में रोबोटिक सर्जरी की उम्र अभी 5-7 साल हुई है। हम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देख रहे हैं, खासकर ऑकोलॉजी, यूरोलॉजी,गाइनेकोलॉजी और थोरासिक सर्जरी में इसका इस्तेमाल हो रहा है।'

बहरहाल इस तरह की सेवाएं देने वाले केंद्र अभी सीमित हैं। उन्होंने कहा, 'इसके उपकरण महंगे हैं, ऐसे में मरीजों पर सर्जरी का बोझ ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में रोबोटिक प्रक्रिया का कवर नहीं मिलता है। ऐसे में मरीज यह विकल्प कम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल करके इसकी लागत घटाई जा सकती है और इसे ज्यादा वहनीय व पहुंच योग्य बनाया जा सकता है।'

बीएस सूडोकू 3620 | परिणाम संख्या 3619

				3		5		8
	7					1	2	
			5		6	4		
		8		9				
	3		2		4		8	
				6		9		
		1	6		2			
	4	2					1	
7		3		5				

4	9	8	6	1	5	3	2	7
5	2	7	3	9	8	1	6	4
6	3	1	7	2	4	8	5	9
8	5	4	2	7	9	6	3	1
9	7	3	1	8	6	5	4	2
1	6	2	5	4	3	7	9	8
3	8	9	4	6	1	2	7	5
7	4	6	8	5	2	9	1	3
2	1	5	9	3	7	4	8	6

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2100/2120, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4425/4450, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1670,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1430, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1515, फ्लेक 1450, डीएमओ 1060, टरपीन लैस बोल्ड 1540

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1200/1300, खुरपा 1150/1180,चाकू 1150/1280, रसकट 900/920, शक्कर 1300/1320, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, सिहोरा 3155, बुढ़ाना 3260, शामली 3215,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1150/1200, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4550, खल: सरसों 2250/2350,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2165/2175, मक्की 2250/2275, बाजरा 1870/1875, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4770/4775,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3850, जौ 2000/2010, सरसों लूज 4150/4200

जोधपुर
गेहूं 2050/2080, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7550/7650, बाजरा (गुजरात) 1975/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4250/4300, काबली चना 4800/6000, मूंग 6200/6500,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2050, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1230, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7200/8200, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8500/9500, दाल मसूर 5700/6200, चनादाल 5200/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5550/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250,चावल 1509 सेला 5150/5250, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4000/4025, हरियाणा 3980/4005, राजस्थान 3930/4000, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2500/2600, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2130/2135, सरसों 4425/4450 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000, कपास देशी 4900/5000, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2600/2650,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2120/2130, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2440/2450, दाल उड़द छिलका 8800/10600, चना देशी 5150/5250, दाल चना 5400/5600, काबली चना 5000/5900, राजमां चित्रा पुणे 7000/8300, चीन 7300/7900,

करनाल
गेहूं दड़ा 2135/2140, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, सेला 1121 चावल 5600/5650, स्टीम 6000/6150,

हिसार
ग्वार 3800/3850, जौ 1775/1780, सरसों 4250/4300, मूंग 6600/6700, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4300/4350, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9450/9500, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 264

एनआरसी पर स्पष्टीकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्ताहांत पर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर जो बातें कहीं उनसे देश की जनता में भ्रामक संदेश गया है।

इस विषय पर तत्काल स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एनआरसी और हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन से परेशान मोदी ने दिल्ली में एक चुनावी सभा में तीन बातें कहीं।

पहला, उन्होंने दावा किया कि असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में यानी देशव्यापी स्तर पर एनआरसी लागू करने को लेकर कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं हुई। बीते पांच वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ।

दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एनआरसी के लिए न तो कोई नियम जारी किए गए हैं और न उन पर संसद में चर्चा हुई है।

तीसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे अमल में लाने के लिए कोई डिटेंशन कैंप (नजरबंदी शिविर) नहीं बनाए गए हैं। परंतु इन तीनों मोर्चों पर मोदी की बात सच नहीं है।

संसद का 20 नवंबर का रिकॉर्ड बताता है कि गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में असम में समाप्त विवादास्पद एनआरसी प्रक्रिया के तर्ज पर देश भर में एनआरसी लागू करने का सरकार का इरादा जाहिर किया था।

शाह दरअसल 1 मई के अपने ट्वीट को ही दोहरा रहे थे कि पहले सीएए और उसके बाद एनआरसी आएगा। उन्होंने कहा था कि देश से हर घुसपैठिये को बाहर निकाला जाएगा। मई में हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी पार्टी के घोषणापत्र में एनआरसी का प्रमुखता से उल्लेख किया गया था।

इसके अलावा यदि ऐसी कोई पहल नहीं की गई होती तो क्या भाजपा के अन्य बड़े नेताओं से जवाब तलब नहीं किया गया होता? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 दिसंबर को इस संबंध में वक्तव्य दिया था। कर्नाटक जिसने अक्टूबर में कहा था कि वह एनआरसी लागू नहीं करेगा, उसके बारे में जानकारी है कि वहां मार्च 2020 से यह कवायद शुरू करने की चर्चा हुई है। मोदी का यह कहना भी भ्रामक है कि मामला न तो संसद में आया है और न ही नियम बने हैं।

एनआरसी को संसद में लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संबंधित कानून 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पारित हो गया था और विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नामांकन के रूप में प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। जहां तक डिटेंशन सेंटर की बात है तो गुवाहाटी, नवी मुंबई, बेंगलूरु और पश्चिम बंगाल में दो स्थानों पर इसके निर्माण के लिए जगह चिह्नित कर ली गई है।

सच्चाई और वक्तव्य में इतनी विसंगति से आम जनता की चिंता दूर होने वाली नहीं है। यह संभव है कि मोदी ने भाजपा के सहयोगियों समेत व्यापक विरोध से निकले संदेश को समझ लिया हो और उन्हें लगा हो कि जनता का मिजाज ठीक से समझ नहीं पाए।

भारी बहुमत पाने के बाद अक्सर नेताओं से ऐसी चूक हो जाती है। चूंकि वह सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए संभव है रैली में उनका वक्तव्य इस बात का संकेत हो कि फिलहाल के लिए एनआरसी को टाल दिया गया हो। यदि ऐसा है तो लाखों नागरिकों को अनिश्चितता में धकेलने के बजाय इस विषय में स्पष्ट वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए।

यकीनन पांच वर्ष तक बहुसंख्यकवादी बातों को दोहराने के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से यह सुनना वाकई अच्छा लगा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। यदि वह देश के इस बुनियादी मूल्य पर अमल करने का निर्णय करें तो और भी बेहतर होगा।

अजय मोहंती

वित्तीय क्षेत्र में रेटिंग सुधारने का तिलिस्म

किसी देश की रेटिंग का ताल्लुक सेवा क्षेत्र को ऋण देने की उसकी क्षमता एवं उत्सुकता से बुनियादी तौर पर होना चाहिए। इसकी अहमियत बता रहे हैं **टी टी राम मोहन**

रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स (एसऐंडपी) ने भारत के लिए चेतावनी जारी कर दी है: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की हालत सुधारें या रेटिंग में कटौती के लिए तैयार रहें। मूडीज ने पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को 'स्थिर' से बदलकर 'नकारात्मक' कर दिया है। एसऐंडपी ने वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि के 5.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने आर्थिक वृद्धि दर के इस साल 4.9 फीसदी रहने की बात कही है। महज दो साल पहले किसने सोचा होगा कि भारत की जीडीपी वृद्धि छह फीसदी से भी नीचे आ जाएगी?

संभावित डाउनग्रेड की चेतावनी देने के लिए रेटिंग एजेंसियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। खबरों का प्रवाह काफी डरावना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) अक्टूबर में 3.8 फीसदी ऋणात्मक रहा था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई नवंबर में एक साल पहले की तुलना में 5.5 फीसदी बढ़ गई। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 3.3 फीसदी रहने के बजट लक्ष्य से पार जाना तय ही है। वित्तीय क्षेत्र में तनाव बरकरार है। कर्ज लेने की दर काफी गिर चुकी है।

एजेंसियों ने अच्छे वक्त में भी भारत को रेटिंग देने के मामले में गलती की है। आर्थिक समीक्षा 2016-17 में कहा गया था कि भारत एसऐंडपी से मिली बीबीबी रेटिंग से बेहतर का हकदार है क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन काफी अच्छा था। एक देश की रेटिंग सेवा ऋण के मामले में उसकी क्षमता एवं उत्सुकता से संबंधित होनी चाहिए। भारत ने बीते वर्षों में अपनी कर्ज देनदारियों में चूक नहीं की है। इसका कर्ज एवं जीडीपी के बीच करीब 65 फीसदी का अनुपात ऊंचा लग सकता है। लेकिन इसे जीडीपी में बाह्य ऋण के अनुपात और इसकी वृद्धि दर के तारतम्य में ही देखा जाना चाहिए। क्या विदेशी लेनदारों को यह लगता है कि आज भारत पर अपनी कर्ज देनदारी पूरा नहीं कर पाने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हमारी वृद्धि दर फिसल चुकी है? यह सुझाव हंसी के लायक ही लगता है।

यह ठीक है कि रेटिंग एजेंसियां कहीं नहीं जाने वाली हैं और रेटिंग में गिरावट हमेशा ही एक सिरदर्द होता है। ऐसे में भारत के लिए चुनौती यह है कि बढ़ी हुई वृद्धि दर दोबारा हासिल की जाए। घाटे के मौजूदा स्तर के हिसाब से देखें तो राजकोषीय राहत देना असंभव नजर आता है। सार्वजनिक इकाइयों (पीएसयू) की परिसंपत्तियों की त्वरित बिक्री कर राजस्व जुटाने की चर्चा चल रही है। लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं है। रणनीतिक बिक्री में मूल्य-निर्धारण एवं बोली लगाने की कठिन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। और वे विवाद से उस समय भी परे नहीं हैं। एयर इंडिया की बिक्री की एक कोशिश 2018 में नाकाम हो गई थी लेकिन अब भी इस दिशा में प्रयास जारी हैं।

मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर की समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती रोक दी है जिससे मौद्रिक सुगमता भी नहीं रह गई है। फिलहाल यह कोई बड़ा मसला नहीं है। यह अधिक अहम है कि अब तक नीतिगत दरों में हुई 135 आधार अंकों की कटौती का कितना हिस्सा नीचे तक पहुंचा है? जमाओं में अचलता असल में पारेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरे कारक भी हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उधारी देने में हिचक सकते हैं क्योंकि कई बैंक न्यूनतम पूंजी जरूरत के करीब काम कर सकते हैं। तेरह सार्वजनिक बैंक विलय के व्यापक दौर से गुजर रहे हैं। इससे भी कर्ज आवंटन में कुछ सुस्ती आई है।

इस तरह अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए दो बड़े वृहद-आर्थिक उपकरण- राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन कुंद हो चुके हैं। लिहाजा सरकार क्षेत्रवार स्तर पर मुद्दों का समाधान करने पर ध्यान देने के मामले में सही है। वित्तीय क्षेत्र में तनाव को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में दो तरह की अच्छी खबरें हैं। पहली, एस्सार मित्तल का आर्सेलरमित्तल द्वारा अधिग्रहण हो रहा है और इससे बैंकों को 42,000 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। एस्सार स्टील को कर्ज देने वाले बैंक अपना बकाया मिलने पर किए गए ऋण प्रावधान को हटा सकते हैं। दूसरी, बैंकों को टाटा समूह, आईसीआईसीआई बैंक और वैश्विक निवेशकों के स्वामित्व वाली इकाई के हाथों प्रयागराज पावर जेनरेशन कंपनी की बिक्री से 6,000 करोड़ रुपये मिले हैं। एकमुश्त समाधान में ऋणदाताओं को इस सौदे में 52 फीसदी नुकसान झेलना था। यह विचित्र है कि इस सौदे का वित्तपोषण भारतीय स्टेट बैंक ने किया है जो खुद नुकसान उठाने वाले बैंकों में शामिल है। अगर बैंकर दिवालिया प्रक्रिया के बाहर बड़ी कर्जदार संपत्तियों के समाधान की कोशिश के लिए आखिर साहस जुटा रहे हैं तो यह एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने सही संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंकरों के वैध कारोबारी निर्णयों पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे।

किफायती एवं मध्यम आय वाली आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) सक्रिय हो चुका है। इस कोष के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। एनबीएफसी की परिसंपत्तियां खरीदने के लिए बैंकों को आंशिक ऋण गारंटी देने की योजना भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने करीब एक लाख करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना के मद में सरकार ने 7,657 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इस योजना के तहत उपलब्ध आंशिक ऋण गारंटी का दायरा बीबीबी रेटिंग वाले एनबीएफसी तक बढ़ा दिया है। पहले यह सुविधा केवल एए या उससे अधिक रेटिंग वाले एनबीएफसी के लिए ही उपलब्ध थी।

दोनों योजनाओं से राहत मिलनी चाहिए लेकिन एक स्तर तक ही ऐसा होगा। एआईएफ के लिए आवंटित राशि काफी कम है और इस योजना को लागू कर पाना भी आसान नहीं है। आंशिक ऋण गारंटी भी बैंकों को बाहर निकलकर एनबीएफसी की परिसंपत्तियां लेने के लिए नहीं उत्साहित करेगी। बैंक इस कर्ज के बड़े हिस्से को लेकर आशंकित होंगे क्योंकि वह असुरक्षित उपभोक्ता कर्ज हैं। रियल एस्टेट कर्जों में आवासीय परियोजनाओं के कर्ज, पट्टा किराया छूट, वाणिज्यिक परिसर और डेवलपर वित्त का जोड़ है। बैंक पहले दो समूहों के प्रति रुचि दिखाएंगे लेकिन इन दोनों उत्पादों के लिए खासी मांग पहले से ही है। ऐसे में बैंकों को एनबीएफसी से ऋणग्रस्त परिसंपत्तियां खरीदने की जरूरत नहीं महसूस हो सकती है। आर्थिक वृद्धि की फिसलन मूलत: इस वजह से आई है कि एक बैंकिंग संकट के बाद एनबीएफसी संकट भी आ गया है। एनबीएफसी क्षेत्र को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना एक लंबी कवायद होने जा रही है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए ध्यान बैंकों पर होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समुचित पूंजी डालना, शीर्ष स्थानों पर त्वरित नियुक्तियां सुनिश्चित करना और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रबंधन को सशक्त करना स्थिति को तेजी से ठीक करने के लिए बेहद जरूरी हैं।

(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं)

अस्वाभाविक समय में भी नैसर्गिक साझेदार हैं अमेरिका और भारत

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

पिछले दिनों वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पांपेओ और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर तथा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात के बाद अमेरिकी मीडिया ने जम्मू कश्मीर संकट और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर लगातार सवाल किए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत को लेकर अमेरिकी अवधारणा बनाने में ये मुद्दे अहम हैं।

दो दशक पहले दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट आने के बाद बार-बार इनके 'नैसर्गिक साझेदार' होने की बात कही जाती है। लगभग हर साझे वक्तव्य में 'साझा मूल्यों' और 'जीवंत लोकतंत्र' होने की बात कही गई है। व्यावहारिक राजनीति करने वाले कहते हैं कि यह बस जुमलेबाजी है क्योंकि अमेरिका का तानाशाहों और अलोकतांत्रिक नेताओं के समर्थन का इतिहास रहा है। अमेरिका जहां दबंग नेताओं और उनके अधिनायकवादी शासन के साथ नीतिगत समझौते करता रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के साथ उसके समझौते साझा मूल्यों और वैश्विक दृष्टि पर आधारित हैं।

कुछ का कहना है कि ट्रंप भारत पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि वह खुद 2017 में चुनिंदा मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर रोक लगा चुके हैं। उनके इस प्रतिबंध को अमेरिकी अदालतों ने तो उलटा ही, अमेरिकी मीडिया, समाज और वहां के सदन के सदस्यों ने भी खारिज किया। ट्रंप अमेरिकी नीति में एक असामान्य घटना हैं। यदि वह 2021 में जीतते हैं तो जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति रहेंगे। यह बात सीनेट में भी प्रतिध्वनित हुई जब प्रतिनिधि सभा में उन पर महाभियोग चलाने की बात उठी।

अमेरिका ने अब तक भारत में मुस्लिमों के विरुद्ध भेदभाव करने या कश्मीरी नेताओं को बंदी बनाए रखने को लेकर कुछ नहीं कहा था। हालिया संवाद में अवश्य पांपेओ ने कहा कि अमेरिका हर जगह अल्पसंख्यकों के संरक्षण और धार्मिक अधिकारों के बचाव को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में इन मसलों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया में निरंतरता रहेगी। भारत की लाज बचाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारतीय लोकतंत्र का सम्मान करता है क्योंकि भारत में खुद इन विषयों पर बड़ी बहस चल रही है।

बहरहाल, भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर अमेरिकी प्रशासन को एक नई तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर अमेरिकी कांग्रेस में भारत के साथ रिश्ते को लेकर द्विपक्षीय सहमति पर भी पड़ेगा। माना जा सकता है कि भारत होने के नाते हमें अमेरिका से जो सहूलियतें मिलती थीं वे बंद हो सकती हैं। भारत के लिए रूस एस-400 हवाई रक्षा मिसाइल खरीदने को अमेरिकी इजाजत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। वहीं कई मुद्दों पर अब भारत को खुलकर अमेरिका के साथ आना होगा, भले ही भारत के हित उस कदर जुड़े हों या नहीं।

विदेश और रक्षा मंत्रियों के उपरोक्त संवाद के नतीजे आशा के अनुरूप ही थे। अमेरिका ने हिंद-प्रशांत में भारत की सुरक्षा स्थिति का समर्थन किया। भारत ने भी उस सुरक्षा ढांचे का समर्थन करते वक्त चीन की आवश्यकताओं का ध्यान रखा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत के योगदान की सराहना की लेकिन तालिबान के साथ अमेरिका की वार्ता इस बात से विरोधाभासी है। अमेरिका ने ईरान के मसले पर भारत से कहा कि वह अधिकतम दबाव में सहयोग करे। हालांकि उसने भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर सहयोग को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने चीन के 5जी संचार नेटवर्क पर चिंता जताई जबकि भारत के मंत्री खामोश रहे। रक्षा साझेदारी के क्षेत्र में और प्रगति देखने को मिली। औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर अहम हैं। इसके तहत भारत को अहम अमेरिकी रक्षा तकनीक हासिल होगी। दोनों देशों के रक्षा उद्योग में करीबी संबंध कायम होंगे। इस संबंध में वार्ता सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। इससे पहले के दो समझौतों को पूरा होने में एक दशक लगा था।

ऐसे में बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौते (बीईसीए) के रूप में एक ही ऐसा समझौता शेष है जो भारत और अमेरिकी सेना के बीच जानकारियां साझा करने की व्यवस्था को सुसंगत बनाएगा। इससे नेविगेशन और निशाना तय करने की व्यवस्था बेहतर होगी। भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी मंच के सलाहकार विक्रम सिंह कहते हैं कि उम्मीद थी कि बीईसीए को जल्दी मूर्त रूप दिया जा सकगा लेकिन अभी भी चिंता के तमाम विषय बरकरार हैं।

रक्षा रिश्तों में दोनों पक्षों ने रक्षा तकनीक और व्यापार पहल (डीटीटीआई) के तहत तीन समझौतों को अंतिम रूप देने की घोषणा की। इसके तहत अहम तकनीक विकसित की जाएंगी। दोनों देशों के रक्षामंत्रियों और नई दिल्ली स्थित भारतीय नौसेना मुख्यालय तथा हवाई स्थित इंडो-यूएस पैसिफिक कमांड के बीच हॉटलाइन का काम पूरा होने की घोषणा भी की गई। बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक बल की केंद्रीय कमान में एक भारतीय नौसेना अधिकारी की तैनाती की घोषणा भी की गई।

दोनों देश हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों पर करीबी नजर रखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे के यहां अधिकारियों की तैनाती कारगर होगी। इस पर भी सहमति बनी कि अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमांड और अफ्रीकी कमांड के अधिकारियों को साझा प्रशिक्षण दिया जाए।

दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्यिक मसलों पर असहमति के बावजूद रक्षा रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। पारंपरिक तौर पर देखें और पाकिस्तान का उदाहरण लें तो अमेरिका मानवाधिकार और राजनीतिक तथा धार्मिक आजादी पर सुरक्षा साझेदारी चिंताओं को तरजीह देता है। परंतु भारत के लिए यह बेहतर होगा कि वह सहिष्णुता की परीक्षा न ले और उन मूल्यों की ओर लौटे जो अंतरराष्ट्रीय जगत में उसे प्रभावी और स्वीकार्य बनाए रखते थे।

कानाफूसी

मध्य प्रदेश के नाखुश विधायक

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पहली बार विधायक बने 15 नेताओं ने मंत्रियों और अफसरशाहों की बेरुखी से नाखुश होकर एक दबाव समूह बनाया है। उनका इरादा आगे नियमित बैठकें करने और अपनी मांगों, अनुशंसाओं पर उठाए गए कदमों की समीक्षा करने का है। इन नेताओं का यहां तक कहना है कि अगर भविष्य में हालात नहीं सुधरे तो वे अपनी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ तक पहुंचाएंगे। नाराज विधायकों में संजय शुक्ला, सुरेंद्र सिंह शेरा, अशोक मर्शकोले और भूपेंद्र मरावी समेत कई नाम शामिल हैं। वहीं ये विधायक जिन मंत्रियों से प्रसन्न हैं और जिनके यहां इन्हें अधिक तवज्जो मिलती है उनकी भी सूची बनाई गई है। ऐसे मंत्रियों में शहरी विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और वन मंत्री उमंग सिंघार शामिल हैं।

स्टालिन या रजनीकांत?

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन के बेटे और पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष उदयनिधि स्टालिन को सोशल मीडिया पर रजनीकांत का विरोध करने के कारण राजनीतिक विरोधियों और रजनीकांत के प्रशंसकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। रजनीकांत ने ट्विटर पर लोगों को सलाह दी कि वे हिंसा न करें और एकजुट रहें। हालांकि उन्होंने ट्वीट में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन का उल्लेख नहीं किया। उधर लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ द्रमुक के आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करते हुए जूनियर स्टालिन ने 69 वर्षीय अभिनेता रजनीकांत पर हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा कि जो बूढ़े लोग अधिकारों के लिए हो रहे प्रदर्शन को हिंसा का नाम दे रहे हैं, वे सुरक्षा के साथ अपने घर पर बैठे रहें। इस पर लोगों ने उदयनिधि से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वह अपने पिता की बात कर रहे हैं क्योंकि वह भी 66 वर्ष के हैं।

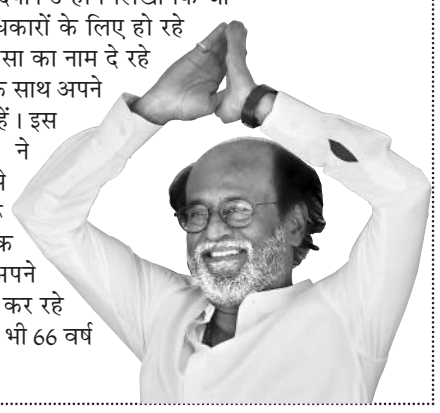

आपका पक्ष

सड़क हादसे रोकने के लिए हों उपाय

देश में सड़क हादसों में एक दिन में जितने लोग जान गंवाते हैं उतने तो आतंकवाद के शिकार नहीं होते हैं। सरकार को सड़क हादसे रोकने के लिए भी उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना कि देश की सुरक्षा के लिए आतंकवाद को लेकर है। सड़क हादसा कभी किसी की लापरवाही से हो जाता है तो कभी दूसरों की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ जाती है। दोपहिया वाहनों की दुर्घटना के आंकड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने वालों को हमेशा हेलमेट पहन कर वाहन चलाना चाहिए। केवल चालान भरने के डर से हेलमेट पहनने की आदत बदलनी चाहिए। सरकार सड़क हादसे रोकने के लिए कानून बनाती है लेकिन इस कानून का पालन वाहन चालकों को करना पड़ेगा। यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान काटने का मकसद किसी चालक को परेशान करना नहीं होता है, बल्कि सरकार का

मकसद उन लोगों को सबक सिखाना होता है जो यातायात नियम तोड़ कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। सड़क पर सावधानी, सतर्कता और यातायात नियमों के पालन से स्वयं तथा दूसरों की कीमती जान को बचाया जा सकता है। अपनी लापरवाही से जब कोई दुर्घटना होती है तो लोग सरकार को दोष देने लगते हैं। अगर हम खुद ही लापरवाही बरतेंगे और हादसों का कारण बनेंगे तो सरकार इस मामले में क्या कर सकती है। सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई कानून नहीं होता है कि एक छोटे से वाहन में संख्या से अधिक यात्रियों को बिठा दिया जाए। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए आम लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। जिन लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने का तजुर्बा न हो वे वाहन न चलाएं और जिस वाहन में सीटों की संख्या जितनी हो उसमें उतनी सवारी बिठाई जानी चाहिए। अगर कोई निजी वाहन चालक सीटों की संख्या से अधिक यात्रियों को वाहन में चढ़ाता है तो यात्रियों को ऐसे वाहन में बैठने से मना कर देना चाहिए। अगर छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार को विशेष उपाय करने चाहिए

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

ट्रंप के गले का फांस बना महाभियोग

वर्ष 2020 का अमेरिकी चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपनी राष्ट्रवादी नीतियों के चलते अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का भी पूरा जोर ट्रंप को हराने पर है। ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपतियों एंड्रू जॉनसन व बिल क्लिंटन को महाभियोग से क्लीन चिट मिल गई थी वैसे ही ट्रंप को भी इस महाभियोग से क्लीन चिट मिल जाएगी। मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग सफल होते देखकर त्यागपत्र दे दिया था। विपक्षी प्रत्याशी जो बाइडन पर यूक्रेन के जरिये चरित्र हनन कराने का आरोप लग रहा है इसी तरह वर्ष 2016 के चुनाव को रूस के जरिये प्रभावित कराने का आरोप लग चुका है। प्रतिनिधि सभा में विपक्षियों को बहुमत हासिल है लेकिन सीनेट में नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद ट्रंप के क्रियाकलापों से खासे नाराज हैं और इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

गेहूं की रिकॉर्ड बुआई से लहलहाये खेत

रबी सीजन में इस साल कुल रकबा 536.21 लाख हेक्टेयर पहुंचा जो पिछले साल 504.69 लाख हेक्टेयर था

सुशील मिश्र
मुंबई, 23 दिसंबर

रबी फसलों की बुआई का रकबा पिछले साल के पार पहुंच चुका है। इस सीजन की सबसे महत्त्वपूर्ण फसल गेहूं की बुआई इस साल रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। चालू सीजन में अभी तक गेहूं बुआई का रकबा 278 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है जो चालू रबी सीजन के सामान्य बुआई आंकड़े का 90 फीसदी है। तिलहन को छोड़कर सभी फसलों की बुआई पिछले साल से बेहतर है। चालू सीजन में अभी तक फसलों का कुल रकबा पिछले साल की अपेक्षा 32 लाख हेक्टेयर से भी अधिक है।

इस साल अच्छी और देर तक बारिश होने के कारण खेतों में नमी होने का सबसे ज्यादा फायदा गेहूं की फसल को मिला है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 20 दिसंबर तक देश में गेहूं की बुआई रकबा 277.91 लाख हेक्टेयर हो गया है जबकि पिछले साल इस समय तक 250.02 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। रबी सीजन के दौरान गेहूं का कुल सामान्य रकबा 305.58 लाख हेक्टेयर माना जा रहा है। अर्थात सीजन के सामान्य रकबा के 90 फीसदी क्षेत्र में गेहूं की बुआई हो चुकी है। चालू सीजन में गेहूं की बुआई पिछले साल की समीक्षाधीन अवधि के मुकाबले 27.88 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक गेहूं की बुआई पिछले साल की समान अवधि से अधिक होने के साथ 19 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह की सामान्य बुआई रकबे से भी अधिक है। इस समय तक का सामान्य रकबा 262.26 लाख हेक्टेयर है।

चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई नया रिकॉर्ड बना रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 19 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह तक इस साल देश में 277.91 लाख हेक्टेयर, 2018-19 में 250.02 लाख हेक्टेयर, 2017-18 में 253.61 लाख हेक्टेयर, 2016-17 में 266.39 लाख हेक्टेयर, 2015-16 में 260.51 लाख हेक्टेयर और 2014-15 में 275.51 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी।

चालू सीजन में गेहूं का सामान्य रकबा 305.58 लाख हेक्टेयर है जबकि कृषि मंत्रालय ने चालू सीजन में गेहूं बुआई का लक्ष्य 317.40 लाख हेक्टेयर तय किया है।

गेहूं के रकबे में बढ़ोतरी की वजह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बुआई पिछले साल से अधिक होना है। बुआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी तक मध्य प्रदेश में 67.54 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो चुकी है जबकि पिछले साल 45.95 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के 84.09 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इस साल 84.19 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। हालांकि गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य पंजाब और हरियाणा में इस साल बुआई पिछले साल से कम है। अभी तक पंजाब में 34.08 लाख हेक्टेयर और हरियाणा में 23.87 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है।

गेहूं की तरह दूसरी फसलों की भी बुआई पिछले साल की अपेक्षा बेहतर दिखाई दे रही है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी सीजन में अभी तक धान का रकबा 12.35 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है, जो पिछले साल 10.11 लाख हेक्टेयर था। दलहन फसलों की भी बुआई पिछले साल के 131.38 लाख हेक्टेयर से कुछ अधिक 131.46 लाख हेक्टेयर हो गई है। मोटे अनाजों का रकबा 42.70 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है जो पिछले साल 40.10 लाख हेक्टेयर था। हालांकि तिलहन फसलों की बुआई पिछले साल से कुछ पिछड़ी हुई है। तिलहन फसलों की बुआई 71.79 लाख हेक्टेयर में हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक 73.08 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। कुल रबी फसलों की बुआई का रकबा भी पिछले साल 504.69 लाख हेक्टेयर की अपेक्षा इस साल 536.21 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है। रबी सीजन के फसलों का सामान्य रकबा 633.98 लाख हेक्टेयर है।

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों और कृषि जानकारों का कहना है कि चालू रबी सीजन की बुआई पिछले साल के अपेक्षा बेहतर रहने वाली है। साथ ही उत्पादन भी बेहतर होगा क्योंकि खेतों में पर्याप्त नमी है और ठंड भी अच्छी पड़ने लगी है जो रबी की फसलों विशेषकर गेहूं की लिए अच्छा है।

गेहूं का रकबा

वर्ष	रकबा
2014-15	275.51
2015-16	260.51
2016-17	266.39
2017-18	253.61
2018-19	250.02
2019-20*	277.91

रबी सीजन का रकबा

फसल	2018	2019
धान	10.11	12.35
दलहन	131.38	131.46
मोटे अनाज	40.10	42.70
तिलहन	73.08	71.79
गेहूं	250.02	277.91
कुल	504.69	536.21

*19 दिसंबर तक, रकबा लाख हेक्टेयर में, स्रोत- कृषि मंत्रालय

रियल-टाइम सूचकांक मूल्य प्रसारण शुरू

एमसीएक्स ने जारी किए नए जिंस सूचकांक

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 23 दिसंबर

- कंपनी ने दो खंडों - सराफा और धातु सूचकांक में वायदा कारोबार करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को आवेदन भेजा
- सेबी की मंजूरी पर निर्भर इस डेरिवेटिव करोबार की शुरुआत जनवरी या फरवरी में होगी
- नए सूचकांकों का यह नया सेट उस मौजूदा सेट का स्थान ले लेगा जिसे कुछ साल पहले थॉमसन रॉयटर्स के साथ मिलकर विकसित किया था

देश के सबसे बड़े जिंस एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) ने इस मंच पर कारोबार किए जाने वाले जिंस वायदा अनुबंधों के आधार पर नए सूचकांकों की श्रृंखला जारी की है।

एमसीएक्स के एक अधिकारी ने कहा कि एक्सचेंज ने रियल-टाइम सूचकांक मूल्य प्रसारित करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने दो खंडों - सराफा और धातु सूचकांक में वायदा कारोबार करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को आवेदन भेजा है। सेबी की मंजूरी पर निर्भर इस डेरिवेटिव करोबार की शुरुआत जनवरी या फरवरी में होगी।

एक आंतरिक अनुसंधान और विकास दल द्वारा विकसित ये सूचकांक सेबी और इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्युरटीज कमिशंस (आईओएससीओ) के मानकों के अनुरूप हैं। नए सूचकांकों का यह नया सेट उस मौजूदा सेट का स्थान ले लेगा जिसे कुछ साल पहले थॉमसन रॉयटर्स के साथ मिलकर विकसित किया गया था।

एमसीएक्स ने खंड और जिंस विशेष से संबंधित सूचकांक भी पेश किए हैं जिन्हें विनियामक द्वारा अनुमति दिए जाने पर कारोबार के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। एमसीएक्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पीएस रेड्डी ने कहा कि हमें विश्वास है कि जब इन सूचकांकों पर उत्पादों (उदाहरण के लिए वायदा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ आदि) की शुरुआत की जाएगी, तब सभी वर्ग के निवेशक काफी कम लागत वाले तरीके से जिंस/जिंस खंडों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 23	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,770.5	0.8	1,938.5	-2.5
Copper	6,155.5	8.1	6,433.5	4.4
Nickel	14,220.0	-19.9	15,030.2	-18.0
Lead	1,909.0	-8.5	2,219.4	6.4
Tin	17,260.0	4.0	17,980.1	0.4
Zinc	2,341.0	1.7	2,598.7	-0.4
Gold ($/ounce)	1,482.6*	-2.6	1,665.8	0.8
Silver ($/ounce)	17.3*	-7.1	19.7	-4.1
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	65.9*	3.1	66.8	4.7
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-11.9	2.2	-11.8
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	187.4	10.6	303.7	4.3
Maize	177.8*	-1.1	332.6	12.3
Sugar	357.8*	8.7	483.5	-1.9
Palm oil	722.5	35.7	1,130.8	29.4
Rubber	1,567.2*	2.8	1,840.1	2.4
Coffee Robusta	1,335.0*	2.6	1,868.2	-9.9
Cotton	1,504.4	14.1	1,581.5	-3.2

* As on Dec 23, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.2 & 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	73.9	12349
Oil and Oilseeds	174.4	83790
Spices	0.9	16
Metal(Dec 20)		
Metal- non ferrous	5351.4	57784
Metal- precious	8224.5	427
Oil and gas(Dec 20)		
Gas	2856.3	40630
Oil	13107.6	2126

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	212.8	111152
Grains	156.0	100710
Oil and Oilseeds	751.7	514395
Others	96.5	69725
Pulses	182.6	46860
Spices	47.9	27705

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3335.3	3.8
Natural Gas (Dec 26)	165.8	3.2
Nickel (Dec 31)	1054.4	1.7
Kapas (Apr 30)	1119.5	1.0
Crude Palm Oil (Dec 31)	742.1	0.6
Silver Mini (Feb 28)	44928.0	0.2
Losers (* % Change)		
Crude Oil (Jan 17)	4294.0	-1.5
Mentha Oil (Dec 31)	1277.3	-0.9
Copper (Dec 31)	442.1	-0.8
Gold (Feb 05)	37991.0	-0.3
Zinc (Dec 31)	183.2	-0.3
Gold Mini (Jan 03)	38002.0	-0.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Chana-Bikaner (Jan 20)	4578.0	2.5
Soyabean Indore (Jan 20)	4408.0	1.6
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4647.0	0.9
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1121.0	0.9
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	911.6	0.8
Guar Seed 10 (Jan 20)	4172.0	0.6
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2181.0	0.6
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7618.0	0.6
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4364.0	0.3
Losers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6048.0	-0.8
Jeera Unjha (Jan 20)	16085.0	-0.4
Coriander-Kota (Jan 20)	6367.0	-0.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19140.0	1.4
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3860.0	0.9
Lead Mum (Dec 31)	153.3	0.4
Lead Min Mumbai (Dec 31)	153.3	0.3
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1277.3	-9.1
Aluminium Mum (Dec 31)	134.3	-4.1
Alumini-Mumbai (Dec 31)	134.3	-4.0
Copper Mum (Dec 31)	442.1	-2.3
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3335.3	-2.3
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	-2.1
Zinc Mini Mumbai (Dec 31)	183.1	-0.5
Zinc Mumbai (Dec 31)	183.2	-0.5

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2055.0	1.8
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6048.0	0.8
Bajra-Delhi (Jan 20)	2055.0	0.7
Moong-Merta City (Jan 20)	7017.0	0.7
Maize-Sangli (Jan 20)	2124.0	0.3
Discount over spot price(In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6367.0	-6.2
Jeera Unjha (Jan 20)	16085.0	-1.6
Soy Bean Indore (Jan 20)	4408.0	-0.7
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7618.0	-0.7
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	750.1	-0.7
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3216.0	-0.3

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	104 (98)
Aluminium ingots /kg	138 (136)
Brass sheet cutting /kg	323 (321)
Brass utensil scraps/kg	306 (306)
Copper heavy scrap /kg	425 (425)
Copper utensil scraps/kg	400 (400)
Copper wire bar /kg	458 (458)
Lead ingots /kg	158 (158)
Nickel Cathodes /kg	1070 (1050)
Tin slabs /kg	1280 (1285)
Zinc slabs /kg	185 (185)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10629 (10714)
DCH - 32 /Qtl	11304 (11220)
Jaydhar /Qtl	10095 (10039)
Shankar- 6 /Qtl	11079 (11023)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	925 (926)
Castor Comm /10kg	915 (916)
Ricebran oil/10kg	760 (760)
Groundnut oil /10kg	1133 (1115)
Linseed oil /10kg	900 (900)
Karanji /10kg	780 (780)
Palm oil /10kg	800 (795)
Sunflower exp ref /10kg	880 (880)
Sunflower oil exp /10kg	855 (850)
Soyabean ref / 10kg	880 (875)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3282-3602 (3282-3602)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	60.34 (60.44)
Brent Crude (UK)	65.92 (66.57)
Brent Crude (WTI)	60.41 (60.41)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu (2.33)	2.23
Furnace/ 180 Cst &/bbl	277.09 (279.98)
Naptha spot /Rs/MT	45170 (45170)
LSHS spot/ M.T.	36150 (36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950 (33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	38128 (37968)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38281 (38121)
Silver.999/ kg	45035 (44250)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	Price (₹.) PClose	Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18808.90	18811.85
Alumini-Mumbai (M)	1 K	140.00	139.95
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2040.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1999.15	2019.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2120.70	2131.00
Brass-Jamnagar (M)	1 K	312.90	321.50
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3267.00	3467.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4427.50	4416.65
Castor Seed-Kadi (N)	X	4355.00	4355.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4364.50	4460.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4580.85	4668.75
Chana-Akola (N)	X	4400.00	4525.00
Coriander-Gondal (N)	X	6600.00	6575.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6871.25	6750.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6871.35	6787.70
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2144.15	2205.10
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2169.05	2246.95
Cotton-Kadi (N)	1 B	18668.45	18721.55
CPO-Kandla (M)	10 K	739.00	741.40
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	747.75	755.30
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	895.00	892.30
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1545.90	1549.80
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3448.75	3461.05
Gold Ahm (M)	10 G	37957.00	38128.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30488.00	30625.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3810.00	3826.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7667.50	7675.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4103.15	4122.30
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4025.00	4100.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1204.90	1202.25
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	94.10	94.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16850.00	16850.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16354.55	16354.55
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1041.00	1056.25
Kapas-Rajkot (N)	X	1041.80	1069.85
Lead Mum (M)	1 K	152.90	152.75
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2052.20	2051.90
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2390.70	2407.80
Maize-Erode (N)	X	2083.35	2094.45
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2250.00	2230.00
Maize-Sangli (N)	X	2115.40	2117.50
Moong-Merta City (N)	1 Q	6950.00	6966.65
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4720.25	4823.25
Nickel Mumbai (M)	1 K	1045.30	1056.70
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3197.00	3197.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3225.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	353.60	352.80
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35550.00	35500.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	818.00	831.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2035.00	2058.15
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	805.00	805.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	896.80	903.95
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	884.55	880.25
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	909.25	915.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13125.00	13100.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44222.00	45018.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4437.00	4441.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4343.00	4340.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4403.60	4469.25
Soy Bean-Akola (N)	X	4384.00	4429.00
Soymeal Indore (N)	1 T	35600.00	36300.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	897.00	901.80
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	28620.00	28900.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	29300.00	29820.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26750.00	27110.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3295.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3333.35	3383.05
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3266.80	3286.65
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3438.10	3519.05
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3250.00	3350.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3100.00	3113.35
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6047.75	6000.00
Wheat Delhi (N)	1 Q	2270.65	2280.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2144.00	2154.40
Wheat New Indore (N)	1 Q	2225.00	2225.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2110.00	2095.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2190.00	2210.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4937.25	4937.25
Zinc Mumbai (M)	1 K	185.15	184.00

* as on Dec 20, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (सोमवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19190, 19250, 19090, 19140	2670	472	4409
Jan 31	19490, 19500, 19250, 19370	3537	549	6501
Feb 28	19650, 19710, 19560, 19600	208	31	561
Mar 31	19950, 19960, 19950, 19960	09	2	21
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2202, 2222, 2174, 2181	54460	3807	64380
Feb 20	2223, 2246, 2194, 2202	18070	1572	37950
Mar 20	2230, 2266, 2220, 2224	2820	275	4550
Apr 20	2248, 2269, 2248, 2248	100	10	180
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1115, 1122.5, 1115, 1119.5	152	36	840
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1114.5, 1123, 1114.5, 1121	2062	1021	4092
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2055, 2055, 2055, 2055	10	1	40
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
May 20	1720, 1720, 1720, 1720	100	1	1000
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4154, 4208, 4154, 4172	30340	3530	78480
Feb 20	4198, 4248, 4198, 4220	6855	1005	20205
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4374, 4374, 4352, 4364	3915	405	29115
Feb 20	4378, 4386, 4366, 4380	1345	198	6315
Mar 20	4348, 4382, 4348, 4366	180	24	5550
Apr 20	4350, 4370, 4350, 4358	285	30	745
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	743.5, 745.8, 738.7, 742.1	5460	421	23250
Jan 31	747, 750.2, 746, 748.6	10180	697	51140
Feb 28	751.6, 753.3, 748.5, 749.9	1000	93	9070
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1280, 1292.1, 1250.4, 1277.3	229.32	544	198.36
Jan 31	1304.1, 1304.1, 1280.1, 1287.7	162.72	377	121.68
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4619, 4655, 4618, 4647	11310	793	19290
Feb 20	4609, 4633, 4599, 4605	1270	99	2400
Apr 20	4548, 4570, 4540, 4549	1880	135	8550
May 20	4569, 4569, 4569, 4569	10	1	400
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	908.6, 913.2, 905.8, 911.6	19655	1954	54100
Feb 20	920, 920, 902, 909.2	10745	1074	42055
Mar 20	892, 906, 892, 903.6	2090	296	6715
Apr 20	888, 895, 888, 895	65	11	50
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4354, 4418, 4342, 4408	47995	5216	154695
Feb 20	4442, 4448, 4364, 4438	24885	3092	135930
Mar 20	4434, 4472, 4404, 4464	6290	959	42735
Apr 20	4468, 4510, 4456, 4502	3450	367	5750
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7594, 7675, 7594, 7618	8600	1289	55120
Feb 20	7702, 7771, 7698, 7719	3985	519	14490
Mar 20	7800, 7800, 7800, 7800	10	1	115
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4512, 4595, 4500, 4578	32580	2382	39470
Mar 20	4450, 4535, 4450, 4514	7550	591	6950
Apr 20	4450, 4500, 4450, 4461	110	11	380
May 20	-, 4463, -, 4463	10	1	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3309.5, 3341.7, 3309.5, 3335.3	0.5	4	10.5
Feb 14	3200, 3277.5, 3200, 3277.5	2.1	20	4.5
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6444, 6470, 6325, 6367	1950	168	9930
Apr 20	6810, 6861, 6761, 6786	260	25	5030
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	16170, 16200, 16000, 16085	870	244	2163
Mar 20	15770, 15930, 15770, 15860	117	39	360
Apr 20	15850, 15850, 15650, 15650	6	2	72
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6106, 6140, 6010, 6048	2245	395	6975
Apr 20	5992, 6048, 5942, 6000	680	124	3160

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	134.1, 134.25, 133.9, 134.1	3140	428	5340
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	134.55, 134.55, 133.95, 134.15	2051	1392	2374
Jan 31	135.3, 135.75, 135.1, 135.5	1780	1161	3811
Feb 28	136, 136, 135.6, 135.8	2	2	4
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	441.4, 441.4, 440.1, 441	10887.5	3590	9310
Jan 31	445.9, 446.6, 445.5, 446.4	5647.5	1807	7640
Feb 28	449.9, 451.15, 449.9, 450.65	12.5	5	72.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153, 153.5, 152.8, 152.85	3380	569	3325
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.15, 153.4, 152.9, 152.95	1599	1293	1594
Jan 31	152.3, 152.55, 152.1, 152.5	975	711	2782
Feb 28	156.45, 156.45, 151.55, 153.55	7	5	9
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1050.1, 1053.8, 1047.2, 1051.8	8844	5239	2727
Jan 31	1051.1, 1055, 1048, 1052.9	1342.5	814	1144.5

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Feb 28	1050, 1050, 1050, 1050	1.5	1	3
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	182.6, 182.7, 181.45, 182.05	12105	2005	9940
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.9, 182.9, 181.45, 181.95	4394	3405	4114
Jan 31	182.2, 182.2, 180.65, 181.25	6689	3546	12030
Feb 28	182.45, 184, 181, 181.2	36	33	53
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	38040, 38200, 38040, 38181	4.93	3938	16.34
Apr 03	38150, 38263, 38129, 38259	0.18	153	4.11
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30535, 30574, 30506, 30551	0	116	0
Jan 31	30555, 30619, 30546, 30608	0	146	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37999, 38183, 37999, 38157	0.5	4241	0.84
Feb 05	38025, 38196, 38025, 38167	0.2	1594	0.38
Mar 05	38010, 38170, 38010, 38155	0	12	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3862, 3869, 3845, 3846	0	688	0
Jan 31	3855, 3861, 3850, 3859	0	517	0
Feb 28	3841, 3890, 3826, 3855	0	27	0
Mar 31	3745, 3745, 3745, 3745	0	1	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45051, 45480, 45051, 45400	267.84	7485	362.01
May 05	45542, 45911, 45542, 45858	2.04	67	5.94
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44999, 45490, 44999, 45406	28.44	19307	30.05
Apr 30	45380, 45930, 45380, 45841	1.49	1189	2.28
Aug 31	47500, 47500, 47500, 47500	0	1	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45000, 45492, 45000, 45408	89.5	13785	61.97
Apr 30	45525, 45900, 45525, 45843	1.31	249	2.46

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	164, 164, 158.2, 158.4	53796mb	25685	27394mb
Jan 28	163, 163, 159.2, 159.8	17930mb	9472	22630mb
Feb 25	160, 160, 156.1, 157.5	1559mb	1054	4899mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4290, 4306, 4284, 4301	6785bl	39580	3970bl
Feb 19	4295, 4306, 4286, 4304	96bl	841	76bl

सायं सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19090, 19190, 19090, 19170	3125	473	5374
Jan 31	19290, 19420, 19290, 19400	3724	556	6012
Feb 28	19560, 19600, 19560, 19590	234	27	485
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1107.5, 1113.5, 1107, 1111	448	69	848
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1109, 1114, 1104, 1112	1880	1008	3963
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	744, 745.3, 736, 742.1	9850	812	23440
Jan 31	750, 750.4, 739.9, 747.1	20490	1410	49510
Feb 28	750.1, 752.1, 742.7, 749.5	2310	182	8900
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	909.8, 912.6, 903, 907.8	42620	4220	56035
Feb 20	900, 904, 894.6, 901.6	14420	1278	39405
Mar 20	887.4, 890.4, 885, 890.2	1385	129	6425

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	134.55, 134.65, 134.05, 134.25	5900	984	6765
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	134.65, 134.65, 134.05, 134.3	3645	2993	2686
Jan 31	135.25, 135.6, 134.85, 135.45	1741	1119	2639
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	445.5, 445.5, 441.5, 442.1	28575	9616	10675
Jan 31	450.3, 450.5, 447.05, 447.25	3532.5	1207	4072.5
Feb 28	454.1, 454.1, 452.8, 453.35	7.5	3	70
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.2, 153.5, 152.8, 153.3	10970	1789	3165
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 153.4, 152.85, 153.25	5019	4133	1571
Jan 31	152.4, 152.5, 152, 152.35	711	605	2374
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1036.3, 1056, 1031.1, 1054.4	25050	14928	1608
Jan 31	1037.4, 1053.5, 1030.2, 1052.2	1264.5	751	558
Feb 28	1039.3, 1040, 1039, 1039.6	6	4	3
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.55, 183.55, 182.6, 183.15	28535	4562	8845
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183.6, 183.6, 182.55, 183.05	10531	8244	4093
Jan 31	182.3, 182.85, 181.9, 182.4	3116	1983	8626
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	38040, 38120, 37951, 37991	9.2	7724	15.15
Apr 03	38080, 38167, 38000, 38070	0.27	215	3.99
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30500, 30550, 30500, 30535	0	220	0
Jan 31	30465, 30562, 30465, 30543	0	203	0
Feb 28	30664, 30664, 30664, 30664	0	1	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	38076, 38120, 37965, 38002	1.21	10366	0.72
Feb 05	38043, 38115, 37947, 38000	0.28	2333	0.31
Mar 05	38040, 38063, 37930, 37964	0.01	38	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3867, 3870, 3855, 3860	0	1000	0
Jan 31	3850, 3855, 3836, 3854	0	496	0
Feb 28	3831, 3840, 3831, 3838	0	5	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44627, 45097, 44580, 44904	607.77	16590	330.72
May 05	45069, 45555, 45052, 45347	2.73	88	6.12
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44800, 45111, 44603, 44925	74.39	49539	26.33
Apr 30	45141, 45555, 45072, 45360	3.03	2347	1.91
Jun 30	45600, 45910, 45600, 45765	0	4	0.01
Aug 31	47399, 47399, 46999, 47199	0	2	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44740, 45114, 44604, 44928	214.06	33635	39.6
Apr 30	45146, 45562, 45067, 45376	2.38	448	2.17

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	161.4, 167.3, 161.4, 165.8	150584mb	68363	19364mb
Jan 28	162.9, 166.4, 162.8, 165.3	20923mb	10759	17181mb
Feb 25	159.1, 162.5, 159.1, 161.4	1530mb	1133	4085mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4360, 4364, 4276, 4294	29780bl	176458	2066bl
Feb 19	4358, 4362, 4280, 4297	535bl	4461	60bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

विपक्षी एकजुटता का आह्वान

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ सोमवार को 9वें दिन भी जारी विरोध

समरीन अहमद, अभिषेक रक्षित अर्चिस मोहन

फोटोः दलीप कुमार

नई दिल्ली के राजघाट पर सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जुटे कांग्रेस के दिग्गज नेता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुआई वाली सरकार के कारण देश में लोकतंत्र खतरे में है। ममता ने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट होने और 'देश को बचाने' की योजना बनाने का आग्रह किया है।

बनर्जी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों से पैदा हुए मौजूदा हालातों को 'गंभीर' बताया। उन्होंने सभी गैर-भाजपा दलों को एकजुट होने और केंद्र सरकार के 'तानाशाही' के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया है।

कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने भी सभी दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के चुनावी नतीजे दर्शाते हैं कि भाजपा को हराना नामुमकिन नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ लगातार नौवें दिन भी चेन्नई और बेंगलूरु समेत देश भर में विरोध-प्रदर्शन जारी रहे। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी उन गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपने राज्य में एनआरसी को लागू नहीं करने की घोषणा की है। भाजपा के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है कि वे अपने राज्यों में एनआरसी को लागू नहीं करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को एक जन सभा में विपक्ष के बहुत से नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे को लेकर आलोचना की कि उनकी सरकार ने कभी देश भर में एनआरसी को लेकर चर्चा नहीं की।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने मोदी की टिप्पणी पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि यहां तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए देश भर में एनआरसी को लागू करने की सरकार की योजना की बात कही थी। पवार ने कहा, 'अब यह कहना ठीक नहीं है कि कैबिनेट में एनआरसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।'

पवार ने कहा, 'मेरा मानना है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। ऐसी स्थिति से जनता का ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं और ऐसे भाषण दे रहे हैं। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।'

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसे लागू किया जाएगा, लेकिन 'विस्तृत चर्चा' के बाद। उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर न संसद में चर्चा हुई है और न ही कैबिनेट में। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में दावा किया था कि वह एनआरसी लागू करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि इसे देश भर में लागू किया जाएगा।

विपक्षी दल ने ट्विटर पर कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद के लिए आपका स्वागत है, देश आपका इंतजार कर रहा है। यह दुखद है कि आप हमारे देश में उस बढ़ती अशांति के बारे में पहली बार बोले हैं, जो आप घृणा और झूठ से फैलाते हैं। लेकिन विभाजन के मुखिया से उम्मीद भी क्या की जा सकती है।'

एक अन्य कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'प्रधानमंत्री एक चीज कहते हैं। गृह मंत्री कुछ अलग कहते हैं। लेकिन यह सब उदार और सख्त व्यक्ति होने की रणनीति का हिस्सा है। इसमें किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनना चाहिए।'

'भारतीय नागरिकों पर कानून का असर नहीं'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इदाप्पदी पलानिस्वामी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी और उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वे विपक्ष के भ्रम फैलाने वाले प्रचार की जाल में न फंसे। उन्होंने कहा कि सत्तासीन पार्टी अन्नाद्रमुक ने श्रीलंका के तमिलों के लिए भारत में दोहरी नागरिकता की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

सोमवार को विपक्षी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और इसके सहयोगी दलों ने भी चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक विरोध रैली का आयोजन किया। द्रमुक के अध्यक्ष एम के स्तालिन, कांग्रेस नेता के एस अलागिरी, पी चिदंबरम, वाम दल के नेता और क्षेत्रीय दलों ने नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पलानिस्वामी ने कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून का असर किसी भी नागरिक पर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग मुसलमानों के बीच यह अफवाह फैला रहे हैं कि इसका असर नागरिकता पर पड़ेगा। यह पूरी तरह से गलत है। मैं तमिलनाडु के लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि वे इस तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है और वह भविष्य में भी उन्हें सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। *बीएस*

समझौता न करने की जिद ने सरयू राय को दिलाई जीत!

शिखा शालिनी

सरयू राय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया

सोमवार को जब झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना का दौर शुरू हुआ तब दोपहर तक ऐसे रुझान आने लगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास एक स्वतंत्र उम्मीदवार सरयू राय से पिछड़ रहे हैं। इस रुझान के बीच भी दास टेलीविजन चैनलों पर यह कहते नजर आए कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन उन्हें उस वक्त कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था क्योंकि वह अपनी ही सीट बचाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे थे। झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके बागी सरयू राय ही उन्हें कांटे की टक्कर दी। राय सबके आकर्षण का केंद्र थे क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत कर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलकर उनके ही क्षेत्र में तगड़ी मात दी थी।

खबर लिखे जाने तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक भाजपा उम्मीदवार दास को 57, 607 वोट मिले जबकि राय को 42.57 फीसदी यानी 73,332 वोट मिले। झारखंड सरकार में शामिल रहने वाले राय तब सुर्खियों में आए जब उन्हें जमशेदपुर (पश्चिम) सीट से पार्टी ने टिकट नहीं दी जहां से उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता को 10,517 वोटों से हराया था। हालांकि 2009 में वह इस सीट से 2.68 फीसदी मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे।

उन्हें अपने सिद्धांतों और शर्तों पर राजनीति करने वाला नेता माना जाता है जो अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते। राय ने अविभाजित बिहार और बाद में झारखंड के गठन के बाद कई घोटालों का पर्दाफाश किया। उनकी ही कोशिशों का नतीजा रहा कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद और मधु कोड़ा को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। वह जनसंघ के एक घटक युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा भाजपा से जुड़ने से पहले उन्होंने जनता पार्टी और जनता दल में भी अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाशने की कोशिश की। बेशक वह झारखंड में भाजपा सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बन रहे थे। राय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि उन्होंने झारखंड सरकार में अनियमितताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से भी बात की थी और इन दोनों ने समस्या के समाधान का वादा भी किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने इस बागी नेता से दूरी बनाए रखा।

विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की लेकिन उनमें राय का नाम नहीं था। राय कहते हैं कि अगर पार्टी उन्हें साफतौर पर टिकट देने से मना कर देती तो वह खुद ही इस बात की घोषणा कर देते कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन उनके मुताबिक पार्टी ने उन्हें नकारात्मक जवाब दिए बगैर ही उनका अपमान किया। राय ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया जो उनके मुताबिक इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने मीडिया में कहा था कि रघुवर दास दरअसल रघुवर दाग हैं और मोदी डिटर्जेंट और अमित शाह की लाउंड्री भी उन्हें बचा नहीं पाएगी। राय कहते हैं कि उनका भाजपा में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है और वह स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर गुण-दोष के आधार पर किसी अन्य पार्टी का समर्थन करते हुए गलत कामों की आलोचना करेंगे। उनका कहना है, 'राज्य के 30 सरकारी विभाग में से 16 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा था। सभी मलाईदार मंत्रालयों को मुख्यमंत्री ने अपने ही पास रखा। आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है। यह बात हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में भी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पसंद किया।'

उनका कहना है कि सरकार के गलत कामों के खिलाफ वह आंतरिक स्तर पर आवाज उठा रहे हैं लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव तक कुछ न कहने का निर्देश दिया गया था। वह कहते हैं, 'मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि मैं किसी को खुश रखूं। मैंने तो मुख्यमंत्री को यहां तक कहा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह मधु कोड़ा का रास्ता है और जो इस रास्ते पर जाता है वह वहीं पहुंचता है। मीडिया में तो इस बाबत महज 10 फीसदी ही बात आई है बाकी 90 फीसदी बात तो बाहर आई ही नहीं है। उन्हें इस बात की दिक्कत भी रही कि मैं मीडिया में क्यों चला जाता हूं।' बेशक अब उनके निशाने पर दास ही हैं।

ममता सरकार को अदालत से लगा झटका

अभिषेक रक्षित

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस वक्त झटका लगा जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने से जुड़े सभी विज्ञापनों को हटा ले और आगे भी इस तरह का कोई विज्ञापन देने से बचे। एक वकील सोमेन सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित कराए गए विज्ञापनों के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कथिततौर पर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया गया था। इसके अलावा भी लगातार 5 जनहित याचिका दायर कराई गई। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का पुरजोर विरोध किया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नीलांजन भट्टाचार्य ने कहा, 'अदालत ने राज्य सरकार को आउटडोर तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी विज्ञापन सरकारी पोर्टल और सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं। राज्य को ऐसा करना ही होगा।' उनका कहना है कि राजनीतिक दलों का अपना एजेंडा हो सकता है और वे लोकतांत्रिक तरीके से किसी विधेयक या कानून का विरोध कर सकते हैं लेकिन केंद्र द्वारा पारित किए गए कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। भट्टाचार्य ने कहा, 'किसी दल द्वारा राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल कर पार्टी का एजेंडा चलाना गलत है।'

उच्च न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2020 को करेगा। इससे पहले राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बनर्जी को यह सलाह दी थी कि वे इन कथित विज्ञापनों को हटा लें। यह सारी कवायद तब शुरू हुई जब राज्य सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें ममता राज्य के अधिकारियों के साथ बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी राज्य में लागू नहीं होगा। याचियों ने उनके इस रुख पर एतराज जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस तरह के बयान कैसे जारी कर सकती है।

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी को टैग करते हुए कहा, 'अगर सिर्फ ममता बनर्जी ने ही अपनी पार्टी के कुछ शिक्षित सांसद और विधायकों से यह सलाह ली होती कि संविधान के मुताबिक वह केंद्र द्वारा पारित किसी कानून को लागू करने से नहीं रोक सकतीं, तो अच्छा होता और उनका यह जानना जरूरी है कि नागरिकता का विशेषाधिकार केंद्र के पास होता है।'

ममता और उनकी पार्टी ने इस कानून का विरोध करते हुए कई रैलियों में हिस्सा लिया है और उन्होंने केंद्र को चुनौती देने के लिए संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की बात कही है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान में फेरबदल किया। अदालत ने इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने का आदेश भी दिया जिसे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में अफवाह रोकने के लिए बंद करना पड़ा था। इस बीच भाजपा ने कोलकाता में एक बड़ी रैली निकाली जिसका नेतृत्व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को उचित बताते हुए कहा कि इसका फायदा देश को मिलेगा।

हर मिनट 95 बिरयानी मंगा रहे भारतीय

स्विगी द्वारा भारत में खाने की आदतों पर जारी रिपोर्ट में बताया गया कि देश में ऑनलाइन भोजन मंगाने का चलन तेजी से बढ़ा है और बिरयानी के अलावा अलग-अलग किस्म की थाली तथा मिठाइयों के बहुत अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं

पीरजादा अबरार

खाद्य वितरण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्विगी द्वारा भारत में खाने के ऑर्डर की आदतों पर जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों ने प्रति मिनट औसतन 95 बिरयानी या प्रत्येक सेकंड 1.6 बिरयानी का ऑर्डर दिया। स्विगी ने भारत में बिरयानी के स्वाद को 35,056 किस्म एवं स्वाद के साथ देश के घरों तक पहुंचाया। सबसे लोकप्रिय बिरयानी में बोनलैस चिकन बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, मटन बिरयानी, ऐग बिरयानी, वेज बिरयानी और पनीर बिरयानी रहीं।

बिरयानी कॉम्बो के लिए लोकप्रिय केरल के त्रिशूर में इस साल एक नया जायका देखने को मिला। जेल में रह रहे कैदियों ने 'फ्रीडम फूड कॉम्बो' तैयार किया जिसे स्विगी ने घर-घर पहुंचाया। लॉन्च के कुछ समय बाद ही इस कॉम्बो के 2,000 से अधिक ऑर्डर बिक चुके थे। मुंबई की 'चल धन्नो तवा बिरयानी' 19 रुपये में स्विगी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी और यह जल्दी में रहने वाले लोगों के लिए कम समय में मिलने वाला शाकाहारी भोजन था। पुणे की 'चिकन सजुक तूप बिरयानी' 1,500 रुपये के साथ सबसे महंगी बिरयानी थी। बिरयानी के अलग-अलग स्वाद के अलावा साल 2019 में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले व्यंजनों में मसाला डोसा, पनीर बटर मसाला, चिकन एवं वेज फ्राइड राइस, तंदूरी चिकन और दाल मखनी शामिल हैं।

स्विगी की रिपोर्ट कंपनी को मिले लाखों ऑर्डरों के विश्लेषण पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि वह ऑनलाइन भोजन उपलब्ध कराने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। यह विश्लेषण जनवरी 2019 से नवंबर 2019 के बीच की अवधि के लिए किया गया।

आसानी से उपलब्ध भोजन की मांग में भी तेजी देखी गई। वर्ष 2019 में स्विगी पर मिलने वाली खिचड़ी के ऑर्डरों की संख्या में जनवरी से नवंबर के बीच 128 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। नवरात्रि के त्यौहार के महीने में इसमें काफी वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, 'मेथी मलाई पनीर, चावल एवं रोटी के साथ ढाबा दाल, गोभी मटर मसाला, जीरा चावल, रोटी के साथ दाल मखनी और मिनी डोसा, इडली, वड़ा तथा सांभर थाली' जैसी कई थालियों को ग्राहकों के घरों पर पहुंचाया गया।

वर्ष 2019 में 17,69,399 गुलाब जामुन के ऑर्डर मिले तो वहीं हलवे के 2,00,301 ऑर्डर आए। मिठाइयों की श्रेणी में फलूदा को हाल ही में शामिल किया गया और इस साल इसके कुल 11,94,732 ऑर्डर मिले। अकेले मुंबई में फलूदा के 6,000 से अधिक ऑर्डर आए। 'चोको पाइ एंड ड्रिंक' भी काफी लोकप्रिय रहा और अकेले चंडीगढ़ में इसके 79,242 ऑर्डर किए गए। दूसरे लोकप्रिय मीठे पकवानों में चॉकलेट, कोकोनट आइसक्रीम और केसर हलवा शामिल रहे।

भारत में अधिकांश लोग अपनी खाने की आदतों तथा वरीयताओं को लेकर जागरुक हो रहे हैं जिसे ध्यान में रखते हुए स्विगी ने कीटो श्रेणी में भी कदम बढ़ाया है। स्वस्थ भोजन श्रेणी में इस वर्ष 3.5 लाख से अधिक ऑर्डर मिले। फिटनेस के लिए उत्साही लोगों के लिए रेस्त्रां ने अपने मेन्यू के भीतर एक अलग श्रेणी बनाई है और स्विगी को मिलने वाले कीटो संबंधी ऑर्डरों में 306 फीसदी की तेजी देखी गई। स्वस्थ भोजन श्रेणी में सबसे अधिक ऑर्डर किए गए कुछ व्यंजनों में 'कीटो ब्राउनी, कीटो-फ्रेंडली टस्कन चिकन और हेल्दी रेड राइस पोहा' जैसे व्यंजन शामिल रहे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत ग्राहकों के लिए कीटो ब्राउनी अच्छी मिठाई है। यह देखा गया है कि कीटो समेत स्वस्थ भोजन श्रेणी में 249 प्रतिशत की तेजी हुई है। स्विगी ने नेस्पर्स, डीएसटी ग्लोबल और टेसेंट से 1.5 अरब डॉलर की राशि जुटाई है। कंपनी को ग्राहकों से अजीब तरह की सिफारिशें भी मिलती हैं। इसमें डेंगू मरीज के लिए पपीते के पत्ते पहुंचाना, ऑक्सीजन मास्क पहुंचाना, मंदिर का प्रसाद आदि शामिल हैं। स्विगी गो के जरिये पहुंचाए जाने वाले सामानों में दस्तावेज से लेकर कपड़े, खाना, चाबी, फोन तथा लैपटॉप चार्जर, हेलमेट, चश्मे शामिल रहे। कंपनी ने बताया, 'बेंगलूरु के हमारे एक डिलिवरी पार्टनर ने बाइक की चाबी पहुंचाने के लिए 34 किलोमीटर का सफर तय किया। इसमें भी खाना प्राथमिकता पर रहा और स्विगी गो के तहत भेजे जाने वाले लोकप्रिय सामानों में भोजन या लंचबॉक्स शामिल रहा।'

उबर की सवारी

भारतीयों द्वारा ऑनलाइन टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी उबर का उपयोग करने के तरीकों को लेकर कंपनी ने 'हाउ इंडिया मूव्ड इन 2019: ईयर इन रिव्यू' नामक एक रिपोर्ट जारी की।

वर्ष 2019 के दौरान सबसे अधिक उबर राइड वाले पांच शहर

1. दिल्ली एनसीआर
2. बेंगलूरु
3. हैदराबाद
4. कोलकाता
5. मुंबई

सुबह 2-5 बजे के बीच सबसे अधिक बार उबर का सफर करने वाले शीर्ष 5 शहर

1. मुंबई
2. सूरत
3. अहमदाबाद
4. पुणे
5. कोच्चि

वर्ष 2019 के दौरान विदेश में भारतीयों द्वारा उबर इस्तेमाल करने वाले शीर्ष 5 शहर

1. लंदन
2. सैन फ्रांसिस्को
3. दोहा
4. ढाका
5. टोरंटो

वर्ष 2019 में विदेशी यात्रियों द्वारा सबसे अधिक उबर राइड वाले शीर्ष 5 शहर

1. दिल्ली एनसीआर
2. मुंबई
3. बेंगलूरु
4. हैदराबाद
5. कोलकाता

वर्ष 2019 के दौरान सबसे अधिक बुकिंग दर्ज कराने वाले दिन

1. 7 दिसंबर
2. 6 दिसंबर
3. 30 नवंबर
4. 29 नवंबर
5. 15 नवंबर

उबर पूल का इस्तेमाल करने वाले शीर्ष 5 शहर

1. बेंगलूरु
2. दिल्ली
3. कोलकाता
4. हैदराबाद
5. मुंबई

उबर के लिहाज से सबसे अच्छे त्योहार
1.होली 2. दशहरा 3. दीपावली